

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6» शिवलिंग पूजन में रखें ध्यान...



## जुलाई में खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट

पांच साल बाद चार प्रतिशत से नीचे पहुंचा आंकड़ा

नई दिल्ली। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो लगभग पांच वर्षों में पहली बार रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे है। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण यह गिरावट आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में गिरकर 3.54 प्रतिशत पर आ गई, जो जून 2024 में 5.08 प्रतिशत और जुलाई 2023 में 7.44 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 5.42 प्रतिशत रही, जो जून में 9.36 प्रतिशत थी। पिछली बार मुद्रास्फीति सितंबर 2019 में 4 प्रतिशत से नीचे थी। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सीपीआई मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का काम सौंपा है, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत का स्वीकार्य मार्जिन होगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही हैं, जून में खाद्य मुद्रास्फीति साल-दर-साल लगभग दोगुनी हो गई है। यह 2023 के इसी महीने के 4.63 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8.36 प्रतिशत हो गई। खाद्य पदार्थों की कीमतों में यह लगातार

वृद्धि भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती रही है, जिनका लक्ष्य खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना है। हालांकि, हाल ही में मुद्रास्फीति के आंकड़े इस लक्ष्य की ओर प्रगति का संकेत देते हैं। मई में, वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर आ गई, जो अप्रैल में 4.83 प्रतिशत से थोड़ी कम है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने पिछले साल दिसंबर में 5.7 प्रतिशत दर्ज किया था, लेकिन तब से इसमें नरमी आ रही है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के आरामदायक क्षेत्र के भीतर रही है, लेकिन यह पहले आदर्श 4 प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर थी। मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय रही है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन भारत ने अपनी मुद्रास्फीति को दिशा को अपेक्षाकृत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। जून को छोड़कर, महीने-दर-महीने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आरबीआई द्वारा लगातार नौवां बार रेपो दर को अपरिचित रखने के निर्णय के बाद आई है। मई 2022 से, आरबीआई ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर में संघीय रूप से 250 आधार अंकों की वृद्धि की है।

## 450 हेलीपैड, करोड़ों का खर्च, नवीन के करीबी

पांडियान के खिलाफ एक्शन में भाजपा सरकार

नई दिल्ली। ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना और राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पिछले साल फरवरी से सितंबर के बीच नौकरशाह से राजनेता बने वीके पांडियान द्वारा की गई हेलीकॉप्टर यात्राओं की विस्तृत जांच की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वे जानना चाहते हैं कि इन यात्राओं के लिए 450 हेलीपैड कैसे बनाए गए, प्राधिकरण प्रक्रिया क्या थी और इन यात्राओं के लिए किसने धन मुहैया कराया।

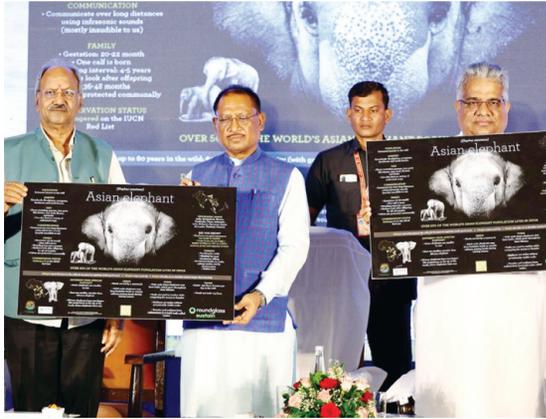
नई दिल्ली। ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना और राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पिछले साल फरवरी से सितंबर के बीच नौकरशाह से राजनेता बने वीके पांडियान द्वारा की गई हेलीकॉप्टर यात्राओं की विस्तृत जांच की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वे जानना चाहते हैं कि इन यात्राओं के लिए 450 हेलीपैड कैसे बनाए गए, प्राधिकरण प्रक्रिया क्या थी और इन यात्राओं के लिए किसने धन मुहैया कराया।

# हाथियों के संरक्षण में भारत अग्रणी : भूपेन्द्र

रायपुर। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर स्थानीय होटल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की भागीदारी से किए गए प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाथियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका रही है। केन्द्रीय मंत्री श्री यादव ने हाथियों के संरक्षण एवं मानव कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय जुड़ाव (क्रॉस सेक्टरल एंजगेजमेंट) की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम हाथियों को बचाएंगे तो वन भी समृद्ध होंगे, क्योंकि हाथियों को 'पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर' के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में मानव-हाथी द्वंद को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, हाथी परियोजना के निदेशक श्री रमेश पाण्डेय तथा छत्तीसगढ़ के



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री वी. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी श्री सुधीर अग्रवाल, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, वन्यप्राणी विशेषज्ञ, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कृषि, विद्युत एवं रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी और सुरक्षित संख्या है। हाथियों की

पिछली गणना अखिल भारतीय समन्वित हाथी गणना अनुमान 2017 के अनुसार, भारत में 29 हजार 964 हाथी हैं। भारत में हाथी गलियारों से संबंधित 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व (ईआर) और 150 हाथी गलियारे हैं।

भारत में हाथियों को विभिन्न खतरों से कानूनी रूप से बचाने के लिए सर्वोत्तम कानून बनाए गए हैं। हमारे देश में हाथियों के संरक्षण के लिए एक सुदृढ़ बड़ी और सुरक्षित संख्या है। हाथियों की संस्थागत ढांचा भी मौजूद है।

## लोगों को जम्मू कश्मीर में शांति, विकास के लिए नुकसानदेह लोगों को मजबूत नहीं करना चाहिए

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से ऐसे तत्वों का समर्थन नहीं करने का आग्रह किया है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश में शांति और विकास के लिए नुकसानदेह हों। सिन्हा ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने को ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए यह भी दावा किया कि इस कदम के बिना आधी आबादी अपने अधिकारों से वंचित रह जाती। उन्होंने रविवार को 'पीटीआई-वीडियो' के साथ साक्षात्कार में कहा, "मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वे शांति और विकास के लिए नुकसानदेह तत्वों को मजबूत न करें।" जेल में बंद नेता इंजीनियर राशिद के संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने को लेकर कुछ राजनीतिक दलों की आलोचना और इससे लोकतांत्रिक राजनीति में अलगाववाद बढ़ने की आशंका को लेकर सिन्हा सवालों का जवाब दे रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा, "यह सच है कि ऐसे तत्व संसद तक पहुंच गए हैं। देश उन्हें जानता है और हम भी उन्हें जानते हैं। लोकतंत्र में पूरी तरह आजाद मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि वे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।" राशिद ने बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद 18वां लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राशिद ने बारामूला में नेशनल कॉन्फेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया।

## मेघालय के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री शाह को भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। शाह को अवैध आब्रजन के मामलों को रोकने के लिए सीमा पर लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के बारे में भी जानकारी दी गई। दिल्ली में बैठक के दौरान संगमा के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग भी थे। संगमा ने कहा, आज हमने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों की समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शाह को बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सेना के साथ मिलकर सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा, मेघालय पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और हमने उन्हें सूचित किया है कि सीमा क्षेत्र में समग्र सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। संगमा ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र अवैध आब्रजन को अनुमति नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। शाह को अवैध आब्रजन के मामलों को रोकने के लिए सीमा पर लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के बारे में भी जानकारी दी गई। दिल्ली में बैठक के दौरान संगमा के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग भी थे। संगमा ने कहा, आज हमने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों की समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शाह को बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सेना के साथ मिलकर सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा, मेघालय पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और हमने उन्हें सूचित किया है कि सीमा क्षेत्र में समग्र सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। संगमा ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र अवैध आब्रजन को अनुमति नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

शिलांग। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। शाह को अवैध आब्रजन के मामलों को रोकने के लिए सीमा पर लगाए गए रात्रि कर्फ्यू के बारे में भी जानकारी दी गई। दिल्ली में बैठक के दौरान संगमा के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग भी थे। संगमा ने कहा, आज हमने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों की समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शाह को बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सेना के साथ मिलकर सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा, मेघालय पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और हमने उन्हें सूचित किया है कि सीमा क्षेत्र में समग्र सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। संगमा ने कहा कि शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र अवैध आब्रजन को अनुमति नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।



## छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले दो नए अतिरिक्त न्यायाधीश

बिलासपुर। हाईकोर्ट में दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इन दो जजों में अधिवक्ता विभू दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम से नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि, यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत की गई है। दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यलयों का कार्यभार संभालने की तारीख से दो साल के लिए रहेगा। इस संबंध में भारत सरकार के कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इन दोनों न्यायाधीशों के नाम बार कोटे से तय किए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अभी 22 जज हैं, जिनमें 17 स्थायी और 5 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। अब हुई इन नई नियुक्तियों से न्यायालय की न्यायिक क्षमता बढ़ेगी और न्यायिक कार्य को ज्यादा सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पारामर्श के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।

## पूर्व केन्द्रीय मंत्री चिदंबरम अल्ट्राटेक सीमेंट की पैरवी करते पहुंचे छग हाईकोर्ट

बिलासपुर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे। वे अल्ट्राटेक सीमेंट की पैरवी करने हाईकोर्ट आए थे। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की डिविजन बेंच में हुई, हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, बलौदाबाजार जिले में स्थित रेलवे साइडिंग के उपयोग को लेकर अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट आमने-सामने हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम तो श्री सीमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता रविन्द्र श्रीवास्तव ने पैरवी की। हाईकोर्ट में मामले की आज अंतिम सुनवाई थी। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

## अंगदान के लिए रायपुर में बना ग्रीन कॉरिडोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 9वां अंगदान हुआ है। रामकृष्ण अस्पताल में आज ब्रेन डेथ घोषित होने पर गोसाई परिवार ने 54 वर्षीय मुन्नी गोसाई का अंगदान कर 5 लोगों की जान बचाई है। मुन्नी के फेफड़े को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुणे की 45 वर्षीय महिला को दान कर उन्हें नया जीवन दिया गया। मुन्नी गोसाई के बच्चे बताते हैं कि उनकी मां का जन्म राजनंदगांव में हुआ था और वो बहुत ही नेक दिल इंसान थीं। शुरू से ही अपने अंगों को दान में देने के लिए उत्साहित थीं। उन्होंने और उनके परिवार ने कई बार रक्तदान जैसे नेक कार्यों में भी भाग लिया है। मुन्नी का पूरा परिवार गडई का रहवासी है। मुन्नी गोसाई का अचानक तबियत खराब होने पर उन्हें गडई में ही भर्ती किया गया, मगर वहां वेंटीलेटर की सुविधा न होने की वजह से उन्हें 10 तारीख की सुबह रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती किया गया। 11 अगस्त को रामकृष्ण अस्पताल ने उन्हें ब्रेन डेथ घोषित किया, जिसके बाद परिवार की सहमति से अंगदान की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें एक किडनी एम्स रायपुर को और एक किडनी रामकृष्ण को डोनेट किया गया।

## पुरानी पेंशन पर 11 लाख जवानों-अफसरों को झटका

क्रा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के उन 11 लाख जवानों/अधिकारियों के लिए झटका है, जो सुप्रीम कोर्ट से पुरानी पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे थे। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की गृह की है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), सीसीएस (पेंशन), 1972 के अनुसार, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महोदेवन को पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए भारत संघ को अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया है। इसके तहत प्रतिवादियों/सीपीएफ कर्मियों की याचिकाओं का निपटारा उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया था। सीपीएफ में ओपीएस लागू करने के लिए ये याचिकाएं पवन कुमार एवं अन्य के द्वारा दायर की गई थी। बता दें कि पवन कुमार मामले में यह माना गया था कि केन्द्रीय अर्धसैनिक बल, संघ के सशस्त्र बल हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है।

## सपा नेता नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप, गिरफ्तार

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को सोमवार को 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को 112 हेल्युलाइन नंबर पर लगभग देर रात 1.30 बजे एक संकेतपूर्ण कॉल प्राप्त हुई। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि यह कॉल एक युवा लड़की से आई थी जिसने बताया कि उसके कपड़े उतार दिए गए थे और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने लड़की को बचाया और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। वहीं, नाबालिग पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। भाजपा के अमित मालवीय ने इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी एरुकहलाला जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में है नवाब सिंह यादव की पहचान। क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे?

## प्रमुख समाचार

### कल्याणी शंकर

गत दिनों बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक और तेजी से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया, जिससे देश में तत्काल चिंता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण उनकी सरकार गिर गई। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे, बाहरी भागीदारी और एक नाखुश राजनीतिक विपक्ष ने इसे आगे बढ़ाया। हसीना पिछले सोमवार शाम को दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मदद मांगने भारत भाग गई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद को उनके भारत पहुंचने की जानकारी दी। मोदी सरकार को अब बंगलादेश

के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि मोदी ने विदेश नीति में पड़ोस को सबसे पहले महत्व दिया है। नौकरी कोटा के खिलाफ छात्रों के विरोध के कारण हसीना सरकार गिर गई। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। अशांति के परिणामस्वरूप लगभग 560 मौतें हुईं और सैकड़ों बंगलादेशी नागरिक भारत की सीमा पर एकत्र हुए। बेगम हसीना के अचानक चले जाने से बंगलादेश में संभावित शक्ति शून्यता पैदा हो गई है। यह क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। एक समय बंगलादेश की

लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में देखी जाने वाली हसीना ने एक आर्थिक संकट को देखरेख की। हालांकि, बाद में वह अराधित्य और सत्तावादी हो गई, मीडिया आलोचकों पर नकेल कसने लगीं और विरोधियों को जेल में डाल दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद वह पहली राजकीय अतिथि थीं। 1975 में बंगलादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद, हसीना ने भारत में 6 साल बिताए, पदारा पटक में एक छोटे से फ्लैट में रहीं। फिर वह अवामी लीग का नेतृत्व करने के लिए बंगलादेश लौट आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह पिछले साल उनसे 10 बार मिले थे। हसीना

लंबे समय से भारत की मित्र हैं। उन्होंने मोदी के साथ एक सहज संबंध विकसित किया और गांधी परिवार के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी। यह दोस्ती पारस्परिक रही है, क्योंकि बेगम हसीना ने भी भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को खेड़े कर और पागमन सुविधाओं के लिए रियायतें देकर जवाब दिया। छात्रों का आरक्षण विरोधी प्रदर्शन 5 जुलाई को शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में कोटा तय करने के बावजूद, स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी पदों के लिए 56 प्रतिशत आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस कोटे को बढ़ाने के

सरकार के प्रस्ताव के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 200 लोगों की मौत हो गई। बंगलादेश के विपक्षी दल इस मुद्दे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष और विरोध को दर्शाने के लिए एक लंबा मार्च आयोजित किया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आगे की राजनीतिक अस्थिरता को संभावना को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार, हसीना और अमरीका के बीच तनाव तब बढ़ गया जब अमरीका ने उनके देश छोड़ने के बाद उनका अमरीकी वीजा रद्द कर दिया। अमरीकी विदेश विभाग ने बंगलादेश में दीर्घकालिक शांति और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने

में अंतरिम सरकार के महत्व पर जोर दिया, जिससे देश के भविष्य के बारे में आश्वासन की भावना पैदा हुई। हसीना के जाने के बाद, मैडम खालिदा जिया और अन्य विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया गया। जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया ने कभी भी हसीना से सहमति नहीं जताई। बेगम जिया ने जे.ई.आई. के समर्थन से 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यदि नए चुनाव होते हैं तो वे फिर से गठबंधन कर सकती हैं। यह एक प्रश्न चिह्न है कि क्या वे दोनों अपनी पार्टियों का नेतृत्व करेंगी या सेवानिवृत्त होंगी। हसीना के बेटे के अनुसार, वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने

पार्टी के नेतृत्व पर फैसला नहीं किया है। खालिदा के कार्यकाल के दौरान, बंगलादेश और भारत के बीच संबंध कमजोर हो गए। बेगम जिया की जेल से रिहाई उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करने की अनुमति दे सकती है। उन्होंने युवाओं के सपने को विनाश, क्रोध या प्रतिशोध के बिना प्यार और शांति के साथ पूरा करने के लिए एक लोकतांत्रिक बंगलादेश की आवश्यकता पर जोर दिया। नई दिल्ली स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, खासकर सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में। मोदी सरकार बंगलादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आशंकित है। अपदस्थ प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद

बंगलादेश में झूझड़ों को निशाना बनाकर हिंसक घटनाएं हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगलादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का आह्वान किया है। व्यापक हिंसा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच बंगलादेश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। देश आवश्यक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए भारत पर निर्भर है। भारत को नेता के जाने के बाद अपनी बंगलादेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उसने भारी निवेश किया है। तीसरा मुद्दा भारत और बंगलादेश के बीच छिद्रपूर्ण सीमा के बारे में है। बंगलादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों के सीमा पार करने के आरोप लगते रहे हैं।

# अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

■ जंगल वन रहे खेत, गुस्से में ग्रामीण, जंगली हाथियों का बंद रहा आतंक



होकर अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया। इस विरोध प्रदर्शन में वन विभाग के अधिकारी, वन समिति के सदस्य और पदाधिकारी भी शामिल थे।

यह हसदेव अरण्य के बाद दूसरा बड़ा मामला है। जब ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए कदम उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे जंगल को बचाने के लिए किसी भी स्तर पर लड़ने के लिए तैयार

हैं। वन समिति के अध्यक्ष अगस्तुस बेक ने बताया कि जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर जमीन को खेत में तब्दील कर दिया गया है, जहां धान सहित अन्य फसलों की खेती की जा रही है।

ग्रामीण तुलसी, यदुमणि, भुनेश्वर, मुनेश्वर, चूड़ामणि सहित अन्य ने बताया कि वे जंगल पर कब्जा हटाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अनुसार, जब वे जंगल में गए, तो वन विभाग के कर्मचारी भी उनके साथ थे। अधिकारियों ने अवैध कटाई और

जमीन पर कब्जा देखकर आश्चर्य व्यक्त किया।

मौके पर ही सभी ने बैठक कर पंचनामा बनाया और अवैध कब्जे को राजसात करने का निर्णय लिया। पथलगांव रेंजर कृपासिंधु पैकरा ने बताया कि शिकायत मिलते ही जांच टीम गठित कर नाप शुरू कर दी गई है। हालांकि, हाथियों के वन क्षेत्र में आने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है। जांच पूरी होने के बाद वन क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों के इस साहसिक कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जंगलों की रक्षा के लिए लोग एकजुट होकर किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर वन विभाग और प्रशासन की निष्क्रियता चिंता का विषय बनी हुई है।

# सुकमा में आईडी ब्लास्ट होने से एक की मौत

मवेशियों को चराने गई थी कवासी सुक्की

सुकमा। सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों के लगाए गए आईडी का शिकार एक ग्रामीण को होना पड़ा। यहां आईडी की चपेट में आकर एक महिला की मौके पर मौत हो गई। मामला थाना किशोराम के ग्राम डब्बामरका का है। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम डब्बामरका की महिला कवासी सुक्की (27) की नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट के कारण मौत हुई। महिला रोजमर्रा की तरह गाय चराने अपने गांव से निकली थी। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट से ये हादसा हुआ। दो दिन ही नक्सली संगठन ने बीजापुर में आईडी की चपेट में आकर बच्ची की मौत के मामले पर माफीनामा जारी किया था और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की बात कही थी।



सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने इस मामले पर कहा कि नक्सलियों द्वारा मनमाने तौर पर जगह-जगह लगाए गए आईडी की चपेट में आकर निर्दोष ग्रामीणों की मौत के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मामले में नक्सलियों के खिलाफ अपराध थाना किशोराम में पंजीबद्ध किया जा रहा है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

## 10 प्लेटफार्म वाला जोन के पहिला स्टेशन बनिह हमर विलासपुर

विलासपुर। जोनल स्टेशन में अब प्लेटफार्म की कमी से ट्रेनों के पहिए यार्ड में नहीं रुकेंगे। रेल प्रशासन यहां दो नए प्लेटफार्म बना रहा है। आधा काम पूरा हो गया है। फुट ओवरब्रिज से यात्रियों के उतरने के लिए रैंप भी बन रहा है। इसका लोहें खंभा तैयार भी हो गया है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस स्टेशन में 10 प्लेटफार्म हो जाएंगे। विलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। जोनल स्टेशन होने के कारण यहां सुविधाओं का विस्तार भी उसी तरह किया जा रहा है। पिछले साल स्टेशन उस पार के लोगों के



लिए प्रवेश द्वार, टिकट घर व पार्किंग की सुविधा दी गई। अब उस पार के यात्री इस टिकट घर से जनरल टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करते हैं। 450 करोड़ की लागत से यार्ड रिमाडिंग की योजना है। इसमें नया आरआरआइ केबिन से लेकर कई प्रमुख कार्य होंगे। कार्यों की सूची

में एक काम नए प्लेटफार्म का भी है। प्लेटफार्म चार-पांच के बाद दो नए प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, जो नौ व 10 नंबर प्लेटफार्म कहलाएंगे दोनों नए प्लेटफार्म वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इतने ही दिनों का लक्ष्य रेलवे ने रखा है, क्योंकि मापदंडों के अनुसार व सर्वसुविधासुक्त प्लेटफार्म तैयार करना आसान नहीं है। इसका निर्माण चौथी लाइन को देखते हुए भी किया जा रहा है। नए आरआरआइ केबिन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है।

# कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद जगदलपुर में प्रदर्शन

■ मांगा न्याय; आपबीती भी सुनाई

जगदलपुर। मेडिकल कालेज डिमरापाल के डॉक्टरों के अलावा यहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के द्वारा रविवार की रात को कोलकाता के हॉस्पिटल में काम करने के दौरान एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। घटना से देशभर में काम कर रहे डॉक्टरों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है।

इस मामले की निष्पक्ष जांच होने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। डॉक्टर की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति और उसे न्याय मिल सके, इसके लिए डॉक्टरों के द्वारा मोमबत्ती



जलाकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

बता दें कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई। इस

घटना के बाद देशभर में सारे डॉक्टर क्षुब्ध होने के साथ-साथ भयभीत भी हैं। रविवार की रात को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों एवं पीजी रेजिडेंट्स ने पीड़ित महिला डॉक्टर को 101 मोमबत्तियों के साथ मौन श्रद्धांजलि

अर्पित की। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करने के साथ डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के साथ कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा का विरोध भी किया गया। ऐसी हिंसक

गतिविधियों को रोकने के लिए सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी की गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह पहला मामला नहीं है जब ड्यूटी के दौरान किसी डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है, इससे पहले ही कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन किसी भी तरह से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है।

हत्या के अलावा मारपीट को घटनाएं आम बात हो गई है। छत्तीसगढ़ के ही कई मेडिकल कॉलेज में परिरज मारपीट कर चुके हैं, जिसके लिए कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है। लेकिन अबतक इस पर किसी भी तरह से कोई कार्यवाही नहीं किया गया है।

## लकड़ी लेने गए ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला

■ जान बचाने के लिए पहाड़ पर बैठे रहे तीनों, एक की हालत गंभीर



कोरबा। करतला थाना अंतर्गत कोटमेर के जंगल में लकड़ी लेने गए तीन ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में तीन ग्रामीणों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि करतला निवासी चैतराम यादव, सीपत श्रीवास और नईहर यादव लकड़ी लेने गए हुए थे, जहां बैठकर तीनों एक साथ पानी पी रहे थे। अचानक भालू दौड़ते हुए आया और उन पर हमला कर दिया। भालू ने एक के बाद एक तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में नईहर यादव की हालत गंभीर है।

घायल चैतराम यादव ने बताया

ही रुके हुए थे, जहां कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना गांव में जाकर दी।

मदद के लिए ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। घटनास्थल तक पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम था। लिहाजा 112 की टीम ने लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर घायल को दो किमी तक पैदल चलकर वाहन तक लाए, फिर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार जारी है। वन विभाग के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही वह भी घटनास्थल पहुंचे और इस संबंध में जानकारी ली गई। घायल का हाल-चाल जानने के बाद वन विभाग के द्वारा दी जाने वाली तात्कालिक सहायता राशि दी गई है।

## श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी

कवर्धा। भोरमदेव मंदिर से दर्शन कर वापस घर लौट रहा पिकअप वाहन ग्राम हरमो के पास सरोदा मार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे मैदान पर जा पलटा। इस हादसे में एक 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिसमें चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार येमेटला जिला के ग्राम किरकी के महिला, बच्ची समेत 20-22 लोग रविवार की सुबह दर्शन के लिए भोरमदेव पहुंचे थे। पूजा अर्चना व दर्शन के बाद दोपहर करीब 3 बजे पिकअप वाहन से ही ग्राम छपरी की ओर से सरोदा जलाशय की ओर घूमने लिए निकले। लेकिन ग्राम हरमो के पास मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे से नीचे मैदान पर जा पलटा। इससे 11 वर्ष की वैष्णवी पिता सुरेंद्र साहू वाहन की नीचे ही दब गई, जबकि अधिकतर लोग एक-दूसरे पर जा गिरे। बच्चे और महिलाओं को अधिक चोटें आयीं। काफी मशकत के बाद बच्ची को निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

## हाईकोर्ट ने आरोपी मधुर साहू को दी जमानत

■ सलमा सुल्ताना हत्याकांड: कक्षा- प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं



सुकमा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरबा की चर्चित हत्याकांड सलमा सुल्ताना के हत्या के आरोपी मधुर साहू को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पर्याप्त नहीं होने पर जमानत दी है।

दरसअल, कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र की रहने वाली एंकर सलमा सुल्ताना 2018 में लापता हो गई थी। दो महीने बाद सलमा के परिजनों ने कुसमुंडा पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच और तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। पूरे पांच साल

गुजर गए, लेकिन सलमा का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सलमा के दोस्त व जिम संचालक मधुर साहू निवासी बिलासपुर के साथ सलमा के प्रेम संबंध की जानकारी पुलिस को मिली।

पुलिस को पता चला कि मधुर बिलासपुर से आकर कोरबा में जिम खोलकर उसका संचालन करता है। साथ ही उसकी जान पहचान सलमा से थी। इसके बाद पुलिस ने मधुर की नौकरानी से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए बताया

कि सलमा की हत्या 2018 में की गई थी। हत्याकांड में सलमा का दोस्त जिम संचालक सहित कुछ अन्य युवक भी शामिल हैं। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ में संदेहियों ने सलमा की हत्या कर उसके शव को कोरबा-दर्री मार्ग पर स्थित भवानी मंदिर के पास दफनाने की बात कबूल की। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी जिम संचालक फरार हो गया था। जून माह में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जिस जगह पर सलमा को दफनाया गया अब उस जगह पर फोरलेन सड़क बन गई है। पुलिस ने शव निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन ली और फिर खुदाई कर कंकाल को निकालकर डीएनए के लिए भेजा दिया था।

## बुरजी-पुसनार के जंगल से 3 नक्सली गिरफ्तार



बीजापुर। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षाबलों ने गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरजी-पुसनार के जंगल से 3 नक्सलियों जगती पूनेम ऊर्फ जकती ऊर्फ भीमा, सुकारू पुनेम ऊर्फ सुखराम एवं गुट्टा पुनेम को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम, जिलेटिन स्टीक, नक्सली पर्वे, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर बरामद किए गए। गिरफ्तार नक्सली आईडी लगाते, मार्ग अवरुद्ध करने व पम्पलेट-बैनर लगाने की वारदातों में शामिल थे। यह कार्रवाई डीआरजी बीजापुर, बस्तर फाइटर और थाना गंगालूर की संयुक्त टीम ने की है। गंगालूर थाना में गिरफ्तार तीनों नक्सलियों के विरुद्ध कायवाही उपरत आज न्यायिक रिमांड पर न्यायलय के समक्ष पेश किया गया है।

## मिक्सर मशीन में मसाला डालने के दौरान मजदूर का कटा हाथ

जगदलपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मेटावाड़ा खासपारा में सोमवार की सुबह एक नवनिर्मित मकान बनाने के लिए मजदूरों को लाया गया था। यहां एक मजदूर ने जैसे ही मिक्सर मशीन में मसाला डालने की कोशिश की तो उसका हाथ ही कट गया। घटना के बाद मौके में हड़कंप मच गया। घायल को डायल 112 की मदद से महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित फूलमन कश्यप (28) पुत्र सोनुराम कश्यप निवासी मेटावाड़ा खासपारा अपने पड़ोस के अजय कश्यप के नवनिर्मित मकान पर ढलाई का काम चल रहा था, जिसमें घर ढलाई के लिए मिक्सर मशीन भी मंगाया गया। काम करने के दौरान मिक्सर मशीन में मसाला बनाते वक्त सीमेंट डाल रहा था और मशीन चालू स्थिति में होने से पीड़ित का हाथ मिक्सर मशीन में फंस गया और कट कर अलग हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इलाज के लिए डायल 112 की मदद ली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पीड़ित का दाहिना हाथ कोहनी से अलग हो गया था।

## कचरे का गड्ढा बना खूबसूरत तालाबा, चारों ओर गार्डनिंग

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय के जिला पंचायत परिसर में बड़ा गड्ढा था, जहां पहले लोग कचरा फेंकते थे। वहां युवा आईएस अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ रैना जमील की पहल पर अब स्वरूप बदल चुका है। गड्ढा अब तालाब का सुंदर स्वरूप ले चुका है। वहीं, तालाब के चारों ओर गार्डनिंग भी की गई है, जो तालाब की सुंदरता को चार चांद लगा रही है। पहले लोग जाने से कतराते थे, वहीं अब सुबह-शाम भीड़ लग रही है। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2012 को सरगुजा जिला के अलग होकर बलरामपुर रामानुजगंज जिला का गठन किया गया था। इसके बाद उत्तरीय लगातार जिला मुख्यालय अपने प्रति के ओर बढ़ रहा है। ग्राम अधोरा में जिला पंचायत कार्यालय करीब चार एकड़ में संचालित हो रहा है। जिला पंचायत कार्यालय के पीछे एक बड़ा गड्ढा था, जहां पर लोग कचरा फेंकते थे। स्थिति ऐसी थी कि लोग इधर जाने से भी कतराते थे। जिला पंचायत सीईओ के रूप में युवा आईएस अधिकारी रैना जमीन ने पदभार संभाला।

## केंद्र ने हाईकोर्ट में की 2 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति

बिलासपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अधिवक्ता विभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को वरिष्ठता के क्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत की गई है और दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्षों के लिए होगा। इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उन्होंने विभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को शुभकामनाएं भी दीं, और लिखा, मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

## बोलरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आरोपी फरार

जगदलपुर। जगदलपुर के बस्तर कोसा सेंटर के पास बीती रात एक तेज रफ्तार बोलरो का कहर देखने को मिला। बोलरो सवार ने बाइक सवार को टोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद चारपहिया चालक वाहन को मौके पर छोड़कर ही फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही बस्तर थाना प्रभारी के साथ ही उनकी टीम मौके पर पहुंची शव को पीएफ के लिए भिजवाया गया, जबकि मृतक की शिनाखा में जुट गई है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि भानपुरी की ओर से बाइक सवार बस्तर की ओर आ रहा था कि उसी समय जगदलपुर से बस्तर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बोलरो चालक का कोसा सेंटर के पास आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद बोलरो चालक मौके से भागने की कोशिश की है। उन्होंने बाइक सवार होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। जिसके बाद बोलरो चालक गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गया।

# कोरबा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा

■ हर घर तिरंगा के तहत हो रहे कई कार्यक्रम



कोरबा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आने वाले 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सोमवार को कोरबा जिले में भी इसकी शुरुआत हुई। घंटाघर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को मंत्री लखनलाल देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संघटनाओं के समस्त कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अभियान के

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा जब हम घर में तिरंगा लहराते हैं, तब बच्चे भी पूछते हैं और उन्हें हम एक कहानी की तरह सुनाते हैं कि वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। तब आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। इस दौरान कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

अतिथि पहुंचे मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जनमानस में देश प्रेम का संचार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि 15 अगस्त तक सभी घर में तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा हर घर तक पहुंचे।

आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा दौरान राजनीतिक दल से जुड़े लोग, आम नागरिक के साथ ही कलेक्टर अजीत वसंत सहित जिला प्रशासन के कर्मचारी और बड़ी तादाद में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे। तिरंगा यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर पदयात्रा की।



इस अवसर पर केदार कश्यप ने कहा कि तिरंगा यात्रा देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करती है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आह्वान में प्रत्येक प्रदेशवासी को तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करती है। शीघ्र नेतृत्व के आह्वान पर जिला, विधानसभा, मंडल स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में समाज के लोग बड़ी संख्या में सहभागिता दर्ज

## शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा

कांकेर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आमजनों में देश भक्ति की भावना विकसित करने तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि के उद्देश्य से 09 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के नेतृत्व में जिले के नरहरदेव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर से पुराना बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अधिकारी-कर्मचारी, एन.सी.सी. व स्काउट गाइड, पुलिस जवान शामिल हुए।

## संक्षिप्त समाचार

## राज्यपाल डेका से असम के मुख्यमंत्री सरमा ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार को गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सौजन्य भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री सरमा ने राज्यपाल को राजकीय गमछे से सम्मानित किया। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री श्री सरमा को राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट की। इस अवसर पर श्रीमती रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं।

## जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के तीसरी बार अध्यक्ष बने मोहन

रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित संघ रायपुर के चुनाव में कर्मचारी एकता पैनल को एकतरफा जीत मिली। इस पैनल के सभी उम्मीदवारों ने प्रतिद्वंद्वी पैनल सहकारी युवा शक्ति के उम्मीदवारों को परास्त किया। 10 अगस्त को हुए कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में मोहनलाल साहू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी देवेन्द्र कुमार पांडेय को 156 मतों से पराजित किया। मोहनलाल साहू को 325 व देवेन्द्र कुमार पांडे को 169 मत मिले। अध्यक्ष पद पर मोहनलाल साहू का कब्जा लगातार तीसरी बार बरकरार रहा। वहीं सचिव पद के लिए अविनाश शर्मा को 314 व बसन्त कुमार यादव को 170 मत प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव हिरेदे राम ध्रुव को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने विष्णु प्रसाद वर्मा को 87 मतों से हराया। उपाध्यक्ष उमरा दास टंडन को विजयी घोषित किया गया। उन्हें 309 और निकटतम प्रतिद्वंद्वी दिनेश कुमार पटेल को 180 मत प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद पर सुशील कुमार यदु निर्वाचित हुए। संगठन मंत्री अनिल कुमार वर्मा और ऑफिसर लाल यादव को निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी देवाशीष भद्रा थे।

## सरयूपारीण ब्राह्मण सभा ने मनाई तुलसी जयंती

रायपुर। भक्ति आंदोलन की अलख अगर विश्व में किसी ने जगाई है, तो वह श्रीरामचरित मानस की रचना कर आचार्य तुलसीदास जी ने की है, उक्त बातें डॉ. सुशील त्रिवेदी पूर्व आई ए एस राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तुलसी जयंती पर कही। सरयूपारीण ब्राह्मण सभा रायपुर के द्वारा आयोजित तुलसी जयंती के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में कही। सरयूपारीण ब्राह्मण सभा प्रतिवर्ष तुलसी जयंती पर आयोजन करता है। इसी कड़ी में रविवार को तुलसी जयंती मनाई गई। अन्य वक्ता के रूप में समाज के आचार्य यदुवंशीमणी त्रिपाठी एचएम डॉ. दादुभाई त्रिपाठी ने भी तुलसीदास जी के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सरयूपारीण ब्राह्मण सभा अध्यक्ष डॉ. सुरेश शुक्ला ने कहा कि भगवान श्रीराम को जन-जन व घर-घर तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वह सरयूपारीण समाज के कुलपुरुष बाबा तुलसीदास जी ने की। आधार प्रदर्शन अजय तिवारी ने व संचालन कैलाश तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

## आईपीएस अरुण देव गौतम व नेहा चंपावत के प्रभार बदले

रायपुर। राज्य शासन ने सूबे के दो वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के प्रभार बदले हैं। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस अरुण देव गौतम की गृह विभाग की सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति से वापिस लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा एवं अतिरिक्त सेवाएं छत्तीसगढ़, के पद पर पदस्थ करते हुए, संचालक लोक अभियोजन छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं श्रीमती नेहा चंपावत, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर की सेवायें सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी जाती है।

## राजस्व मंत्री ने सोमनाथ में पूजा अर्चना कर सुख-शांति-समृद्धि की कामना की

रायपुर। राजस्व एवं खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज पवित्र सावन महीना के चौथे सोमवार को सपरिवार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम लखना स्थित सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव का पूजा-अर्चना कर आशिर्वाद लिया एवं प्रदेशवासियों के लिए सुख-शांति-समृद्धि की कामना की।

## नवगठित 5 नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों के लिए दस-दस पद स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पांच नवगठित नगर पालिकाओं और 14 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट पर दस-दस पदों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन ने नवगठित अमलेश्वर, मंदिर हसौद, लोरमी, पंडरिया और बांकी मोंगरा नगर पालिकाओं तथा दाहो, सरसीवा, बेरला, पामगढ़, भिंभोरी, रोहांसी, कोपरा, जनकपुर, पवनी, मरवाही, नरियरा, जरहागांव, लाल बहादुर नगर और पटना नगर पंचायतों के लिए प्लेसमेंट पर दस-दस पद मंजूर किए हैं। इन्होंने सफाई श्रमिकों के पांच-पांच पद तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंप अटेंडेंट, वाहन चालक, भृत्य और श्रमिक के एक-एक पद शामिल हैं।

## साहू समाज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है : साव

## उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ साहू अधिकारी-कर्मचारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में हुए शामिल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू अधिकारी-कर्मचारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्कृष्ट कार्यों से साहू समाज का नाम रोशन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज होने के नाते सभी समाजों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। उन्होंने पहली बार आयोजित प्रदेश साहू अधिकारी-कर्मचारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह को ऐतिहासिक एवं गरिमामय बताया हुए इसके आयोजन के लिए समाज के पदाधिकारियों को बधाई दी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि



साहू समाज को और ज्यादा संगठित होकर सही नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे समाज की प्रतिभाओं को प्रदेश और देश की प्रतिभा बनाने की जिम्मेदारी समाज की है। साहू समाज को नई सोच और जल्द के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने समाज के संगठन में महिला और युवा प्रकोष्ठ के साथ ही अन्य प्रकोष्ठों के गठन पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू ने कहा कि समाज के अधिकारी-कर्मचारी बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज को सही दिशा दिखाने का दायित्व बुद्धिजीवी वर्ग का है। साहू समाज ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। हमें आगे भी इसे जारी

रखना है। सामाजिक संगठन में योग्य लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए हमारी निर्वाचन प्रणाली को बदलने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में साहू समाज के लोगों की सही संख्या का पता लगाने साहू समाज द्वारा सामाजिक जनगणना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को ऐसा काम करना है जिसका अनुसरण अन्य समाज भी करे।

छत्तीसगढ़ साहू अधिकारी-कर्मचारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह को विधायक भोलाराम साहू, ईश्वर साहू, दीपेश साहू, इंद्र कुमार साहू, रोहित साहू, संदीप साहू, मोतीलाल साहू और पूर्व मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष श्री भूषेश साहू, महामंत्री श्री दयाराम साहू और श्री लखन साहू, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री पवन साहू, डॉ. नारायण साहू, इंजीनियर यशवंत साहू, श्री घनश्याम साहू और भागवत कथा वाचिका सुश्री यामिनी साहू सहित साहू समाज के अनेक पदाधिकारी तथा अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

## बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही सरकार : टी राजा

रायपुर। कावड़ यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैदराबाद विधायक टी राजा महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के साथ विश्रामपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान टी राजा ने कहा, विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा पर भले बात ना करे, मोदी सरकार को पकड़ कर हिंदुओं के लिए कदम उठाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हर राज्य में हिंदुत्व को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।

विधायक राजा ने कहा, हम सबको संगठित होकर विदेशी ताकतों को रोकना है। इस उद्देश्य से लेकर छत्तीसगढ़ की धरती पर आए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने पर टी राजा ने कहा, सरकार लव जिहादियों को सबक सिखाने का काम कर रही है। सरकार को और मजबूती देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़

में हिंदू विरोधी ताकतों को कमजोर किया जा सके।

वक्फ बोर्ड को लेकर हैदराबाद के विधायक टी राजा ने कहा, यह वही कांग्रेस है, जिसने भारत के दो टुकड़े कर दिए। वक्फ बोर्ड बनाया, जिसके लैंड 4 लाख एकड़ से लेकर 9 लाख एकड़ से ज्यादा हो गए। गरीबों, मंदिरों की जमीन को कब्जाया। कांग्रेस के कार्यकाल में यह सब हुआ है। इतना लैंड कहां से आए, इसकी इंक्री होनी चाहिए। विपक्ष वोट बैंक के चक्कर में इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है।

बांग्लादेश में हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर टी राजा ने कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में भी हो सकता है। पासपोर्ट बने तो पाकिस्तान चुस जाएगा। मुझ पर कांग्रेस ने इतने केस टोक दिया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। बनेगा तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान चुस जाएंगे।

## स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रायपुर में फहराएंगे तिरंगा

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मनेन्द्रगढ़-विरमिरी-भरतपुर जिला मुख्यालय में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में और डिप्टी सीएम विजय शर्मा बस्तर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंत्रियों के ध्वजारोहण और मुख्य अतिथियों की सूची जारी की गई।

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजनांदगांव में, मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा में, मंत्री दयालदास बघेल महासमुंद में, मंत्री केदार कश्यप दुर्ग में, मंत्री लखन लाल देवांगन कोरवा में, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बलौदाबाजार-भाटापारा में, मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर-चांपा में, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर-रामानुजगंज में,



मंत्री टंक राम वर्मा सांरगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल गरियाबंद में, सांसद विजय बघेल बालोद में, सांसद संतोष पाण्डेय खैरगढ़-गंडई-छुईखदान, सांसद चिंतामणी महाराज जशपुर में, सांसद रूपकुमारी चौधरी बेमेतरा में, सांसद राधेश्याम राठिया रायगढ़ में, सांसद कमलेश जांगड़े सकी में, सांसद महेश कश्यप दंतेवाड़ा में, सांसद भोवराज नाग कांकेर में, सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह नारायणपुर जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता

दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

विधायक पुनु लाल मोहले मुंगेली में, धरमलाल कौशिक गौरेला-पेण्डा-मरवाही में, अमर अग्रवाल कबीरधाम में, भैया चंद्राकर धमतरी में, भैयालाल राजवाड़े सूरजपुर में, विक्रम उसेंडी बीजापुर में, राजेश मृगत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में, किरण देव सुकमा, रेणुका सिंह कोरिया में और लता उसेंडी कोण्डागांव जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगी।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहरा तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज शाम 6 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। जोहरा तिरंगा में कैलाश खेर देशभक्ति भरे गीतों से लोगों में देशभ्रम जगाएंगे।

## गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चेंबर का नाम हुआ शामिल

## मुख्यमंत्री साय ने अपने कर कमलों से चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी व उनकी टीम को स्मृतिचिन्ह एवं मेडल भेंट कर किया सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल, चेंबर के वर्तमान कार्यकाल में चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में 11200 से अधिक चेम्बर सदस्य बनने पर चेंबर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी जी एवं उनकी टीम को स्मृतिचिन्ह एवं मेडल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर रायपुर उच्च विधानसभा विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि आज का दिन बड़े हर्ष का दिन है यह हम सब का सौभाग्य है कि हम आज इस दिन के साक्षी बने हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चेंबर का नाम शामिल होना प्रदेश के व्यापारियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इस इस उपलब्धि और सम्मान को चेंबर टीम प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों को समर्पित करता है। पारवानी ने बताया कि



राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर किसी भी व्यापारिक संगठन द्वारा इस प्रकार का कृतमान स्थापित करना अत्यंत ही कठिन है परंतु छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

रायपुर ने यह मुकाम अपने नाम किया है। चेंबर के 64 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार है कि इस कार्यकाल में 11200 से अधिक चेम्बर सदस्यों जुड़े हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि चेंबर पर और चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी पर व्यापारियों का विश्वास कितना गहरा है। इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।

श्री अमर पारवानी भावुक होते हुए कहा कि यह उपलब्धि चेम्बर के सभी व्यापारी भाइयों की उपलब्धि है। आज के इस उपलब्धि पर मैं समस्त चेम्बर पदाधिकारियों के साथ उन समस्त व्यापारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो आज चेंबर से जुड़कर चेंबर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी, समस्त चेंबर पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश को नई पहचान दिलाई है जो विकसित छत्तीसगढ़ के प्रतिरूप को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत में चेंबर की महती भूमिका को रेखांकित करते हुए

शासन और व्यापारियों के बीच चेंबर एक महत्वपूर्ण कड़ी है और छत्तीसगढ़ चेंबर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना हम सबके लिए गौरव की बात है। इस उपलब्धि हेतु आप सभी ढेर सारी बधाई के पात्र हैं।

इस अवसर पर चेंबर सलाहकार सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र दोशी, परमानंद जैन, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, कार्यकारी महामंत्री कपिल दोशी, चेंबर आईटी सेल प्रभारी कैलाश खेमानी, उपाध्यक्ष महेश दरियानी, कन्हैयालाल गुप्ता, हीरा माखीजा, मनोज कुमार जैन, नरेन्द्र हरचंदानी, भरत जैन, मंत्री, निलेश मुंडडा, शंकर बजाज, जितेंद्र गोलछा जैन, प्रशांत गुप्ता, राजेंद्र खटवानी, जनक वाधवानी, विजय पटेल, अजय अग्रवाल, युवा चेंबर महामंत्री कांति पटेल, उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा, जयेश पटेल, गोल्डी लुनिया, जयराज गुरनानी, कार्यकारी अध्यक्ष कैट वासु मखीजा, युवा कैट अध्यक्ष अर्जुन सिंह, श्रीमती सोनम शर्मा एवं राजेश शर्मा छत्तीसगढ़ हेड/अधिकृत संवाददाता गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सहित व्यापारिगण उपस्थित रहे।

## डिप्टी सीएम साव ने भाजपा के तिरंगा यात्रा के दिन कांग्रेस की संविधान यात्रा को लेकर कसा तंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भाजपा के तिरंगा बंटवारे को लेकर भाजपा स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने जा रही है। इसके लिए भाजपा लगातार हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रही है। इस दिन भाजपा अलग-अलग विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। वहीं कांग्रेस इस दिन संविधान यात्रा निकालने जा रही है। पक्ष और विपक्ष के इन यात्राओं को लेकर दोनों में वार-पलटवार का दौर जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने तिरंगा यात्रा के दिन ही कांग्रेस के संविधान यात्रा निकालने को लेकर तंज कसाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। भाजपा अलग-अलग योजनाओं से सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस नकल कर सकती है, लेकिन उनका देश प्रेम एक दिखावा है। कांग्रेस ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, भाजपा बड़े धूस धाम से तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपक बैज के तिरंगा यात्रा को नागपुर की मुख्य शाखा का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को उनकी बयानबाजी का स्पष्टीकरण मिल चुका है, कांग्रेस वही धिसा पिटा टेप चलाती रहती है। जनता जानती है कि हम देश हित में काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने हमेशा एक परिवार (गांधी परिवार) के हित के सामने देश के हित को अनदेखा किया है, इसलिए कांग्रेस की आज यह दुर्दशा है। दिल्ली में आज कांग्रेस को मोडली कमिटी की बैठक है। कांग्रेस को इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छग में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में जनता के हितों के साथ कुठराघात हुआ, छग के हर वर्ग को प्रताड़ित और परेशान किया गया, छग के लोगों को लूटने का काम किया गया। अब हार पर सिर फुटव्वल होना है और आगे भी होगा। इसके अलावा अंतागढ़ टेप कांड मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सभी को बखूबी पता है, कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक जा सकती है।



## सीजी शराब घोटाला : ईडी का दावा-

## अनवर ढेबर विभाग में रखता था मंत्री की हैसियत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी यूपी एसआईटी के बाद अब ईडी के रिमांड पर हैं। बता दें, विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 अगस्त तक ईडी के रिमांड पर भेजा है। इस दौरान दोनों पूछताछ की जा रही है। मामले में दोनों आरोपियों के गिरफ्तारी के संबंध में ईडी ने कई बड़े खुलासे किये हैं, जिसमें शराब घोटाला के लिए बनाए गए सिंडिकेट, ड्यूटीकेट होलोग्राम और अवैध शराब बिक्री के दावे किए गए हैं।

ईडी ने बयान जारी कर दावा किया है कि अनवर ढेबर ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के साथ मिलकर सिंडिकेट बनाया था। दोनों ने मिलकर पूरे घोटाले की योजना बनाई और अनिल टुटेजा आईएएस के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अनवर ढेबर ने आवकारी विभाग में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति की और इस तरह अनवर ढेबर विभागीय मंत्री की हैसियत रखता था।

ईडी के मुताबिक, अरुणपति त्रिपाठी ने



सरकारी शराब दुकान, जिसे पार्ट-बी कहा जाता है, के माध्यम से बेहिसाब शराब बिक्री की योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। उसने ही 15 जिले, जहां अधिक शराब बिक्री होती थी और राजस्व आता था, उन जिलों के आवकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अवैध शराब बेचने के निर्देश दिए थे। ईडी के अनुसार, एपी त्रिपाठी ने ही विधु गुप्ता के साथ ड्यूटीकेट होलोग्राम की व्यवस्था की थी।

ईडी के दावों के मुताबिक, शराब घोटाले का खेल वर्ष 2019 से 2022 के बीच जारी रहा। घोटाला करने कई तरीके अपनाए गए, उनमें नकली होलोग्राम का इस्तेमाल भी शामिल है। ईडी ने घोटाले को तीन कटेगरी ए बी सी में बांटा है। तीन कटेगरी में जो घोटाला

किया गया, वह इस तरह से है।

पार्ट ए- छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य के निकाय) की ओर से शराब की प्रत्येक पेटी के लिए डिस्टलर्स से रिश्वत ली गई थी। इस पार्ट में सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलरी की शराब को परमित करना था। जो रिश्वत-कमीशन को लेकर सिंडीकेट का हिस्सा हो गए थे।

पार्ट बी- सरकारी शराब दुकान के जरिए बेहिसाब कच्ची और देशी शराब की अवैध बिक्री की गई। उक्त बिक्री नकली होलोग्राम से हुई, जिससे राज्य के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी राशि सिंडीकेट की जेब में पहुंची।

पार्ट सी- कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने के लिए डिस्टलर्स से रिश्वत ली गई और एफएल 10 ए लाइसेंस धारक, जो विदेशी शराब उपलब्ध कराते थे, उनसे भी कमीशन लिया गया।

## छत्तीसगढ़ में अब हाईटेक होगी पुलिस

## फॉरेंसिक साइंस ब्रांच खोलने की तैयारी, गृहमंत्री का बड़ा बयान

गौरेला पेंड़ा मरवाही। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा के पत्रकारों की गिरफ्तारी पर जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के पत्रकार रेत माफिया की मनमानी के कन्हरेज के लिए गए थे लेकिन उल्टा पुलिस ने ही चार पत्रकारों पर गांजा तस्करी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जिसे लेकर डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस बारे में उनकी आईजी से बात हुई है। आईजी ने संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों से चर्चा की है। ये जांच का विषय है। लेकिन यदि पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है तो ये गलत है।

छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं पुलिस कटिबद्ध है। जहां भी आवश्यक होंगे नए चेक पोस्ट खोले जाएंगे। मीडिया के माध्यम से गृहमंत्री ने सभी तस्करों को चेतावनी दी है कि नशे के कारोबार को वो भूल जाए। वहीं फॉरेंसिक साइंस को लेकर भी गृहमंत्री ने बड़ा संकेत दिया है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस का ब्रांच खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए रायपुर के रिव शंकर यूनिवर्सिटी से बातचीत चल रही है। ब्रांच खुलने के बाद जहिल



मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

गृहमंत्री ने स्वीकार किया है कि बस्तर संभाग में नक्सली बट रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सली अब बंद रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सरकार का प्लान बिल्कुल साफ है। स्थानीय स्तर पर जो सूचनाएं आ रही हैं उन्हीं के आधार पर भी आपको बता रहा हूँ। स्थानीय नक्सलियों के आईईडी से मारे जा रहे हैं। वो भी नक्सलियों के बीच नहीं रहना चाहते।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पेंड़ा के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर दर्शन किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश सहित देश में खुशहाली की प्रार्थना की है। ज्वालेश्वर महादेव का दर्शन करने के बात कहा कि वो एक कांवरिया के रूप में महादेव के सामने आए हैं।

## उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के मायने

### विनोद पाठक

देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोधपुर हाईकोर्ट में जजों और वकीलों के बीच में जब यह कहा कि देश में कुछ लोग साजिश के तहत एक नैरेटिव चला रहे हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है, वैसा ही भारत में घटित हो सकता है। धनखड़ ने आगाह किया कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, उनका इशारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुशीद की ओर था, जिन्होंने एक बयान दिया कि ऊपर सब सामान दिख सकता है, लेकिन बांग्लादेश जैसी घटना भारत में हो सकती है। कुछ अन्य विपक्षी नेता भी ऐसे विचार व्यक्त कर चुके हैं। उप राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का इस गंभीर विषय पर बोलना और चिंता जाकई गंभीर विषय है। देश में सबकुछ सामान्य रूप से चल रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीच-बीच में विपक्ष की ओर से ऐसे तत्वों को जरूर हवा दी जा रही है, जिन्हें लेकर चिंता उभरती है। वर्ष 2019 में जब नागरिक संशोधन कानून (सीएए) बना तो दिल्ली के शाहीन बाग में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क रोककर बैठ गए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी कई शाहीन बाग खड़े किए गए, जबकि केंद्र सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया था कि सीएए कानून भारत के किसी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जा रही थी। इस आंदोलन को विपक्ष की तरफ से खूब हवा दी गई। उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में थे तो दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगा तहक भड़क गया था, जिसमें कई लोगों की जान गई। देशद्रोह की धाराओं में कई लोग आज भी जेल में बंद हैं। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इशारा ऐसे ही लोगों की ओर है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कृषि सुधारों को लेकर तीन कृषि कानून लेकर आई थी, जिसे लेकर देश के कुछ भागों में किसानों का आंदोलन खड़ा किया गया। खासकर पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर बैठ गए। सालभर दिल्ली के आसपास कई डेरे डाले रखे। दिल्ली में लाल किले के भीतर तक उपद्रवी पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन आज भी पंजाब में किसान किसी न किसी मुद्दे को लेकर कभी रेल तो कभी हाईवे रोक देते हैं, कभी टोल व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। पंजाब में सबकुछ ठीक चल रहा है, यह कहना मुश्किल है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि पंजाब में चल रहे रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर स्पष्ट कह दिया है कि यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) अधिकारियों और ठेकेदारों को सुरक्षा नहीं दी गई तो 14,288 करोड़ रुपए के 293 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। मणिपुर में हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण दो समुदायों के बीच में उपद्रव आज तक थमा नहीं है, जबकि सरकार और कोर्ट इस मुद्दे को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। सत्ता पक्ष लंबे अरसे से देश में विदेशी शक्तियों की दखलांदाजी की बात को उठاتا आ रहा है। हिंडनबर्ग हो या जॉर्ज सौरास या अन्य विदेशी संस्थाएं, एक नैरेटिव जरूर देश में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। भले सविधान बदलने या आरक्षण खत्म करने की बात हो, जिस पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष ने लड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इन मुद्दों पर स्थिति साफ की, लेकिन एक फेक नैरेटिव जरूर खड़ा करने की पूरी कोशिश विपक्ष की ओर से आज भी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण का निर्णय आने के बाद आंदोलन की सुगन्धग्राहट होने पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय लागू नहीं होगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठा रही थीं, उनकी ओर से इस मुद्दे पर मौन धारण किया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर लौटते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ, उसका प्रभाव भारत पर सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से पड़ेगा, यह बिस्कुल स्पष्ट है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन्दिनों में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए जो उपद्रव और हिंसा मची, उसे दुनिया देख रही है।

### शेखर गुप्ता

हम अक्सर क्रिकेट से जुड़े हालात और रूपकों की मदद से राजनीतिक जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय ओलिंपिक खेल और यूरो कप चल रहे हैं इसलिए हॉकी और फुटबॉल का जिक्र अधिक उचित होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हॉकी या फुटबॉल के खेल में आने वाले बदलाव हमारी राष्ट्रीय राजनीति के परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इनके संकेत संसद के मानसून या बजट सत्र में मिलें हैं।

ओलिंपिक हॉकी के अंतिम आठ के मुकाबले को याद कीजिए जहां भारत को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ करीब 42 मिनट तक केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा था। इसका फायदा उठाते हुए ग्रेट ब्रिटेन ने लगातार हमले किए और भारत सामने आकर खेलने के लिए संघर्ष करता रहा। परंतु जब कभी भारत ने हमला किया तो खेल एकदम नाटकीय रूप से बदला नजर आया। बुरी तरह हाशिये पर धकेले जाने के बाद जबाबी हमले का ऐसा उदाहरण जबरदस्त है। बचाव के पूरे समय गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजनीति में भी इस समय ऐसा ही हो रहा है।

2024 के आम चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति को नए सिरे से संतुलित किया है और यह बात हम 4 जून से जानते हैं। पूरा विपक्ष एकदम हाशिये पर धकेल दिया गया था और नाउम्मीद हो चुका था। तभी उसे जवाबी हमला करने का अवसर मिला। फर्क यह था कि ज्यादातर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि जबाबी हमला इतना तगड़ा और प्रभावी होगा कि विजेता को अपनी योजनाएं और रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस दौरान राहुल गांधी को एकदम अलग ढंग से देखा जा रहा है। ध्यान रहे यह वही राजनेता है जिसका हमारे इतिहास में सबसे अधिक मखौल उड़ाया गया है। अब निष्पक्ष होकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ उन विचारों और प्रचार अभियान के बिंदुओं की सूची प्रस्तुत है जो कांग्रेस के घोषणापत्र से लिए गए हैं—

युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर रोजगार बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेडी दी जाए और इंटरनेट शिप की योजना बनाई जाए। गरीब, बेरोजगारों और किसानों को नकद सहायता दी



जाए। किसानों के लिए सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी हो और उनकी कर्जमाफी की जाए। अग्निपथ योजना पर सवाल। राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और उसके बाद लाभ और सहायता का हर वर्ग को उसकी संख्या के आधार पर आवंटन करना। इनमें से कई को भाजपा ने झूठ बताकर खारिज कर दिया। जाति से जुड़े मुद्दों की अनदेखी कर दी गई और इसके प्रतिवाद में हिंदू विचारों के उभार का सहारा लिया गया। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के जाति जनगणना के बाद वितरण के समाजवादी रुख को सीधे तौर पर 'रेव्यूडी' करार देकर खारिज कर दिया गया। आम भाषा में कहें तो कहा गया कि कांग्रेस मुफ्त उपहारों की मदद से वोट खरीदना चाहती है। अब हमें देखना होगा कि आगे चलकर क्या हुआ।

मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में उन विचारों से तेजी से दूर हुई है जिनके तहत वह राहुल गांधी और कांग्रेस के विचारों को कल्पना से परे और मजाक मानती थी। अब वह उनमें से कई को लागू कर रही है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं— इस बजट में बेरोजगारी को लेकर उल्लेखनीय आवंटन किया गया है और वादे भी किए गए हैं। कंपनियों को अधिक लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और पांच साल में एक करोड़ लोगों को इंटरनेट शिप दिलाने की योजना बनाई गई।

भाजपा की राज्य सरकारें, खासकर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां की सरकारें पहले ही कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने पहले की 14 के मुकाबले अब सभी 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। अगर आप इन दिनों अखबारों में आ रहे पूरे पन्ने के विज्ञापनों को

देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा में मुफ्त उपहारों की झड़ लगी है। 46 लाख परिवारों को केवल 500 रुपये में एलपीजी सिलिंडर दिए जा रहे हैं। स्कूली छात्राओं के लिए निःशुल्क दूध योजना और नहर जल उपकर की माफी। एक लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के सभी सदस्यों को हर माह 1,000 किमी निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। भाजपा दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसी ही योजनाओं का मखौल उड़ा चुकी है।

हरियाणा ने पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को भी छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दिया है। महाराष्ट्र पर ध्यान देना अधिक श्रेयस्कर होगा। वह पहले ही ऐसी रेवडिज़ां घोषित कर चुकी है जो सालाना 96,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेंगी। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं— एक खास आय वर्ग के नीचे की महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा वरकरी संप्रदाय (करीब 16 लाख जातिविहीन लोगों का पंथ) को नकद हस्तांतरण तथा सॉफ्टवेडी दी जाएगी। वरकारियों को अपने सालाना पंद्रहपुर तीर्थ के लिए भी सॉफ्टवेडी दी जाएगी। संभव है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले योगी भी कंवडिडिंयों को भी ऐसी ही सुविधा दे दें। 21 से 65 आयु वर्ग की जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम हो उनको हर माह 1,500 रुपये का स्ट्राइपंड दिया जाएगा। इसकी लागत करीब 46,000 करोड़ रुपये होगी। कक्षा 12वीं पास करने वालों को छह माह तक 6,000 रुपये, डिप्लोमाधारियों को 8,000 रुपये और स्नातकों को 10,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी ताकि वे कौशल प्रशिक्षण ले सकें। पांच लोगों वाले हर परिवार को साल में तीन एलपीजी सिलिंडर निःशुल्क दिए जाएंगे।

इन सभी उदाहरणों से यही पता चलता है कि एक दशक तक रक्षात्मक रहा विपक्ष ही इस समय एजेंडा तय कर रहा है। भाजपा जो पहले ऐसे वितरण का मखौल उड़ाती थी वह अब खुद वोट जुटाने के लिए रेव्यूडी बांटने में लगी है। विपक्ष ने सत्ताधारी दल को अपनी स्थिति बदलने के लिए विवश किया है। अगर आप मानते हैं कि यह केवल चुनाव की वजह से हो रहा है तो हम और ठोस बात उठा सकते हैं और वह है हमारी राजनीति में वैचारिक मुद्दे। प्रयास करते हैं यह जानने का कि क्या

उपरोक्त दलील यहां भी लागू होती है। सन 1989 से ही दो बातें यह तय करती रही हैं कि भारत पर कौन शासन करेगा? एक यह कि क्या धार्मिक आधार पर एकजुट लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा सकता है? या फिर क्या जाति के आधार पर बंटे हुए लोगों को धर्म के आधार पर एक सूत्र में पिरोया जा सकता है? हमने अक्सर कहा है कि बीते 25 सालों से जाति जीत रही है। मोदी के उभार ने जातियों में बंटे हिंदू मतों को एकजुट किया। हिंदुत्व की चर्चा ने तब जोर पकड़ा। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के नारे के साथ इसे चुनौती दी। उन्होंने इसे संसद में उठाया और जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इसे संसद से जाति जनगणना कराएगी। भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है। जाति के मसले पर जवाब नहीं होने के कारण ही भाजपा धर्म पर बहुत अधिक जोर दे रही है। नया वक्फ विधेयक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को 'भूमि जिहाद' की बातें, योगी द्वारा 'लव जिहाद' के मामलों में कानून में संशोधन करके आजीवन कारावास की सजा देने का प्रस्ताव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा एक समुदाय पर आबादी नियंत्रित नहीं करने का आरोप आदि इसी वजह से उठाए गए रक्षात्मक कदम हैं।

मेरे मुताबिक यह भ्रम की स्थिति है क्योंकि आम चुनाव में यह कारगर नहीं रहा। भाजपा फिर जाति के प्रश्न से जुड़ रही है। जाति जनगणना को भूल जाइए, पार्टी तो 2021 में ही होने वाली सामान्य जनगणना तक की बात नहीं कर रही। भाजपा ने खुद पिछड़ी जातियों की उपश्रेणियों की बात की और दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी के अधीन इसके परीक्षण के लिए एक आयोग गठित किया। उसने अब तक रिपोर्ट नहीं दी। अगर उपश्रेणियां बनेंगी तो जाति जनगणना भी करनी होगी। यह राहुल गांधी की जीत होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदू मतों का जातीय विभाजन जोर पकड़ेगा। विपक्ष आराम से प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि उसका किसी हिंदीभाषी राज्य में शासन नहीं है। भाजपा सविधान संशोधन के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्योंकि चुनाव प्रचार में यह बहुत बड़ा मुद्दा था। उसे अभी भी बहुत हासिल है लेकिन वह रक्षात्मक रुख अपनाकर चुनौती देने वालों से निपटने के लिए जुड़ रही है।

### पुराण दिग्दर्शन ....

### परिचयाध्याय

## अविशिष्ट-क्रम (भाग-7)

#### गतांक से आगे...

इसलिए स्पष्ट है कि इसका अन्तिम अंश विलुप्त हो चुका है अथवा पुराणान्तर में इसके दो हजार पद्य सम्मिलित हो गये हों। प्रायः अंश सब का सब असली मार्कण्डेय पुराण है ही- यह सभी समालोचक स्वीकार करते हैं।

**14-वामन पुराण-** जिस ग्रन्थ में चतुर्मुख ब्रह्मा ने कूर्म कल्प के अनुसार त्रिविक्रम भगवान् का चरित्र कहते हुए त्रिवर्ग का प्रतिपादन किया हो वह वामनपुराण है जिसका प्रमाण दश हजार है। उपलब्ध वामनपुराण में यह लक्षण तो सर्वथा घटित होता है, परन्तु पद्यसंख्या में चार हजार की न्यूनता है। कहा जाता है कि इसका %त्तर भाग विलुप्त हो गया अतएव अपूर्ण है।

**15-वाराह पुराण-** हे पुत्रो! सुनो, मैं वाराहपुराण का वर्णन करता हूँ, इसके दो भाग हैं, और यह विष्णु भगवान् की महिमा का सूचक है। मेरा

उपदिष्ट मानव-कल्प का प्रसङ्ग वेदव्यास ने 24 हजार श्लोकों में उक्त पुराण में निबद्ध किया है।

उपलब्ध मुद्रित वाराहपुराण में विष्णु भक्ति प्राधान्य रूप लक्षण ठीक घटता है, तथा भागद्वय का समावेश भी पाया जाता है परन्तु पद्यसंख्या की बहुत कमी है। मुद्रित ग्रन्थ में बारह हजार पद्य अवशिष्ट हैं। या तो इसका बहुत-सा भाग पुराणान्तर में सम्मिलित हो गया अथवा सर्वथा विलुप्त हो गया।

**16-मत्स्य पुराण-** हे द्विजोत्तम ! अब मैं तुम्हारे प्रति मत्स्य पुराण का वर्णन करता हूँ। इस पुराण में वेदवेत्ता व्यास जी ने नरसिंह वर्णन से आरम्भ करके सात कल्पों का वृत्तान्त संक्षेपपूर्वक वर्णन किया है। इसकी पद्य संख्या चौदह हजार है। उपलब्ध मत्स्य पुराण में उपयुक्त लक्षण सर्वथा घटित होता है। पद्यसंख्या भी अन्यून चौदह हजार ही है। इसलिए अहिन्दू समालोचकों ने भी इसकी वास्तविकता स्वीकार की है।



### अकिंत सिंह

अहिल्याबाई होल्कर इंदौर घराने की महारानी थीं। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मनको जी शिंदे और माता का नाम सुशीला शिंदे था। इनके पिता धनगर समाज से थे जो कि गांव में पाटिल की भूमिका निभाते थे। उन्होंने अपनी बेटी अहिल्याबाई को पढ़ाया लिखाया। अहिल्याबाई का बचपन बेहद ही साधारण तरीके से गुजरा। हालांकि उनकी किस्मत ने अचानक ही पलटी खाई। दरअसल, अहिल्याबाई की सादगी और सरलता ने मल्हार राव होल्कर को बेहद ही प्रभावित किया। मल्हार राव होल्कर पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम करते थे। अहिल्याबाई उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बेटे खंडेराव

## आदर्श नारी रानी अहिल्याबाई होल्कर

से इनकी शादी करवा दी। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर राजघराने की बहू बंद बन गईं।

अहिल्याबाई अपना जीवन बेहद सादगी में बिताती थीं। वह एक धार्मिक महिला थीं जिन्हें भगवान शिव में बहुत ज्यादा विश्वास था। वह प्रतिदिन मंदिर जाते थीं। इंदौर राजघराने की महारानी बनने के बावजूद भी अहिल्याबाई ने अपने जीवन की सादगी और सरलता को नहीं त्यागा। अहिल्याबाई अच्छे विचारों वाली महिला थीं जो कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते थीं। यही कारण था कि अहिल्याबाई से उनके ससुर मल्हार राव होल्कर बेहद ही प्रभावित थे। अहिल्याबाई को शिक्षित बनाने के लिए होल्कर ने उनके लिए शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया।



पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई बिस्कुल ही टूट गई थीं। खुद को समाप्त कर लेना चाहती थीं। लेकिन उनके ससुर ने उनका ढाँढस बंधाया। अहिल्याबाई को व्यस्त रखने के लिए मल्हार राव ने राजपाट का काम उन्हें सौंप दिया। हालांकि

अहिल्याबाई ने अपने 17 वर्षीय पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गईं। ससुर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने समाज में कई बड़े काम किए। उन्होंने ससुर की स्मृति में इंदौर तथा अन्य इलाकों में विधवाओं, अनाथ और अल्प लोगों के लिए आश्रम बनवाए। उन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक मंदिर, घाट, तलाब, भोजनालय, धर्मशाला इत्यादि का निर्माण कराया।

काशी विश्वनाथ और महेश्वर मंदिर के अलावा वाराणसी के घाटों का भी उन्होंने निर्माण करवाया। अपने कार्यकाल के दौरान अहिल्याबाई भारतीय संस्कृति के साथ-साथ साहित्यकारों, कलाकारों और गायकों को बढ़ावा देती थीं। राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने महिला सैनिक की भी एक टुकड़ी बनाई। अहिल्याबाई ने मरते दम तक के न्याय के लिए काम किया। यही कारण है कि लोग इन्हें देवी समझने लगे। वे गरीबों और निस्सहाय लोगों की निस्वार्थ होकर सहायता करती थीं।

कुल मिलाकर देखें तो अहिल्याबाई होल्कर ने धर्म के विकास के लिए कई बड़े काम किए। इसके लिए उन्होंने अंधाधुन पैसा भी खर्च किया। अहिल्याबाई होल्कर की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई थी। अहिल्याबाई का भारतीय समाज में आज भी बहुत बड़ा सम्मान है।

# बांग्लादेश में संकट के पीछे कई ताकतें

### प्रो शक्तिश्री धूलिपुड़ी पंडित

बांग्लादेश का हालिया संकट बाहरी हस्तक्षेप तथा चुनाव जीतने एवं लोकतांत्रिक बदलाव लाने में असफल रहे उसके आंतरिक सहयोगियों की भूमिका को इंगित करता है। अवामी लीग सरकार के नाटकीय पतन तथा शेख हसीना के देश छोड़ने से इस क्षेत्र में उथल-पुथल के लगातार जोखिम तथा बाहरी दखल और अंडरुनी गड़बड़ी के खतरे का भी पता चलता है। क्या सड़क पर भीड़ और छात्रों के प्रदर्शन बिना बाहरी समर्थन के हो रहे हैं?

अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे ताकतवर दानदाता स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व को पसंद नहीं करते हैं। उनकी तानाशाहों से खूब बनती है और वे अपने हितों को साधने के लिए धार्मिक अतिवाद, यहां तक कि आतंकियों को भी समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। बांग्लादेश उर्दू थोपने के विरोध में बंगाली होने के अपने धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश स्वाधीनता संग्राम के नेता और देश के पहले राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर्रहमान की पाकिस्तान-समर्थक इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हत्या के बाद वहां यह बहस केंद्र में आ गयी कि बांग्लादेश पहले बंगाली है या इस्लामिक।

अमेरिकी पत्रकार और अकादमिक गैरी जे बास की किताब 'द ब्लड टेलीग्राफ- निक्सन, किसिंजर, एंड ए फॉरगॉटन जेनोसाइड' (2013) ढाका में तत्कालीन अमेरिकी वाणिज्य राजदूत आर्चर ब्लड द्वारा 1971 में भेजे गये एक

टेलीग्राम पर आधारित है। उसमें बांग्लादेश जनसंहार पर अमेरिकी विदेश विभाग के रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए लिखा गया था कि अमेरिकी सरकार लोकतंत्र के हनन और भयंकर दमन की निंदा करने में विफल रही, जिसे कई लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे। यह तार आज भी प्रासंगिक है।

अंतरराष्ट्रीय दानी एनजीओ की भूमिका पर संदेह स्वाभाविक है। जिस गठजोड़- पाकिस्तान का आइएसआइ, अमेरिका और चीन- पर 1971 के जनसंहार का दोष था, इस बार उसी पर शक हो रहा है। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च, 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक दमन के साथ हिंदू और बंगाली विरोधी बांग्लादेश जनसंहार की शुरुआत की थी। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लोग हिंसा को देखकर अर्चिभूत रह गये थे और उन्होंने अमेरिकी सरकार को हस्तक्षेप करने का निवेदन किया। आर्चर ब्लड ने बाद में अपनी सरकार की प्रतिक्रिया को 'भयावह चुपची' की संज्ञा दी थी। उसके बाद ही रोष जताते हुए वह तार भेजा गया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे चीन से कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहे थे।

विभिन्न मुद्दों, जो कई देशों में भी हैं, पर आंतरिक झड़पट बांग्लादेश में शीघ्र ही बहुत ही उग्र और हिंसक हो गया, इसे देखते हुए बाहरी- सरकारी और गैर- सरकारी दोनों- हस्तक्षेप को लेकर चिंता स्वाभाविक है। अधिकतर विश्लेषण में



सामान्य तर्क ही दिये जा रहे हैं और अक्सर विदेशी मिलीभगत की संभावना को परे रख दिया जा रहा है। लेकिन, जैसा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उचित ही कहा है, किसी भी आयाम को मानना या नहीं मानना अभी जल्दबाजी होगी। कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया जा रहा है कि चीन, अमेरिका या पाकिस्तान जैसे सरकारी कारकों की भूमिका हो सकती है। इसके साथ-साथ इस्लामिक आतंकी समूहों और अपने तरह के 'लोकतंत्र' को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे दूसरे तत्वों की भूमिका पर भी विचार करना जरूरी है।

ऐसी रिपोर्टों को इस्लाम विरोधी या अनुदार कहकर खारिज करना उसी तरह खतरनाक हो सकता है, जैसे बिस्ली को देखकर कबूतर इस उम्मीद में आंच बंद कर लेता है कि खतरा अपने-आप टल जायेगा। कुछ खबरों में पिनाकी भड़काव्यं सरकारी दोनों- हस्तक्षेप को लेकर चिंता भावनाएं भड़काने के बारे में बताया गया

देखते हुए अदूरदर्शी साबित हुई है। अब वे आलोचक चुप हैं क्योंकि ऐसी नीतिगत पहलों की दूरदर्शिता स्पष्ट दिख रही है। बांग्लादेश के मसले के पीछे हिंदू विरोध है या भारत को कमजोर करने की सोची-समझी रणनीति, इसे रेखांकित कर पाना कठिन है। पर यह तो स्पष्ट है भारत का आर्थिक, राजनीतिक और भू-राजनीतिक विकास इस क्षेत्र के साथ ठोस संबंधों पर निर्भर करेगा।

भारत के सामने अजीब स्थिति है- क्या उसे अपने पड़ोसियों के साथ गहरा जुड़ाव स्थापित करना चाहिए ताकि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा न हो या फिर उसे दूर रहना चाहिए और उन देशों को अपने मसले स्वयं सुलझाने देना चाहिए? इन दोनों विकल्पों में खतरे भी बहुत हैं। गहरे जुड़ाव को 'बिग ब्रदर' के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे भारत विरोधी भावनाएं बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ, किनारे खड़े रहने से प्रभाव कम हो सकता है, भारत के लिए भी जोखिम बढ़ सकता है और अलग-थलग पड़ने का खतरा भी है।

कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बांग्लादेश के बारे में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था। दिसंबर, 2023 में रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने कहा था कि अगर शेख हसीना चुनाव के बाद सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उनकी सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके कहने का अर्थ यह था कि कुछ साल पहले अरब देशों में हुए प्रदर्शनों की तरह बांग्लादेश में भी स्थिति नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैश्विक आलोचना हालिया घटनाओं को

### आज का इतिहास

- 1898 स्पेनी-अमेरिकी युद्ध : क्यूबा में अमेरिकी और स्पेनिका बल खत्म किया गया।
- 1908 हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया।
- 1920 पोलैंड और रूस के बीच वारसां लड़ाई शुरू हुई।
- 1927 बर्टो थोडोल को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के द तिब्बती किताब ऑफ द डेड के रूप में प्रकाशित किया गया।
- 1936 गोताखोर मार्जोरी गेस्ट्रींग सबसे कम उम्र (13 वर्ष 268 दिन) के ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने।
- 1944 एक सप्ताह के बाद, वोला, वारसां, पोलैंड में नागरिकों की भेदभावपूर्ण हत्या के बाद, एसएस जनरल एरिच वॉन डेम बाच-जेलेव्स्की ने आदेश दिया कि किसी भी शेष पोल को श्रम या एकाग्रता शिविरों में भेजा जाए।
- 1944 फालाइन पॉकेट की लड़ाई का आरम्भ हुआ।
- 1950 कोरियाई युद्ध-उत्तर कोरियाई पीपुल्स आर्मी के सदस्यों ने युद्ध के अमेरिकी कैदियों को कैद कर लिया।
- 1952 मास्को में तेरह यहूदी कवियों को झूठे कबूलनामे के लिए जासूसी के लिए फांसी दी गई।
- 1955 जर्मनी के विख्यात उपन्यासकार थॉमस मैन का निधन हुआ। उन्हें उनके द मैजिक माउन्टेन अर्थात जादुई पर्वत उपन्यास से बहुत ख्याति मिली।
- 1961 संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय समुद्री आयोग की स्थापना की गयी।
- 1964 आईओसी की शर्तां के कारण, अपनी रंगभेदी नीतियों को ध्वस्त करने से इनकार सहित, दक्षिण अफ्रीका को टोक्यो में ओलिंपिक खेलों से रोक दिया गया है। 28 साल के निलंबन के बाद भी 1992 में दक्षिण अफ्रीका को ओलिंपिक में प्रवेश नहीं दिया गया था।
- 1969 डेरी के बोगसाइड क्षेत्र में दंगे भड़क उठे और उत्तरी आयरलैंड के पार फैल गए।
- 1971 सीरिया ने सीमा पर हो रहे विवाद के कारण जॉर्डन के साथ राजनयिक संबंधों समाप्त किया।
- 1972 तेल टैंकरों ओसवेगा गार्जियन और टेक्सानिटा स्टिलबाई, दक्षिण अफ्रीका के पास आपस में टकराए।
- 1981 आईबीएम ने अपने पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर, आईबीएम 5150 का खोलासा किया, जो कि एक मूल आकृति के रूप में 1,600 की कीमत पर बेचा गया था, लेकिन 64 बाइट्स की रैम और एक एकल 5 1/4 इंच की फ्लॉपी ड्राइव के साथ पूरी तरह कार्यात्मक पीसी खरीदने के लिए और इसकी कीमत 3,525 थी।

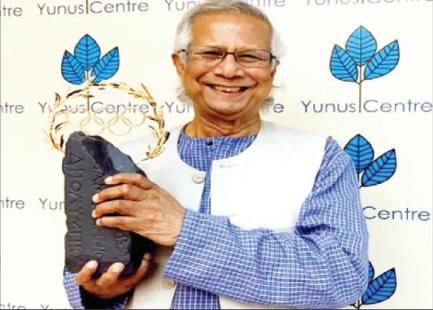
# बांग्लादेश में नया राज, रिश्तों का नया आगाज

## अभिनय आकाश

5 अगस्त 2024 जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास गोणोभवन की तरफ बढ़ती है। पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकते नहीं है। जब तक भीड़ प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंचती है। सेना के बड़े अवसर प्रधानमंत्री से कहते हैं कि अब आपको इस्तीफा देना होगा। हम आपकी सुरक्षा अब नहीं कर पाएंगे। शेख हसीना मामला समझ जाती हैं। वो पहले तो अपना इस्तीफा सौंपती हैं फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका छोड़ देती हैं। वो फिलहाल भारत में हैं। सेना ने सामने आकर कहा कि अंतरिम सरकार का गठन होगा और इसमें अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व होगा। ऐसे में बड़ा सवाल था कि अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन होगा। क्या सेना खुद कमांड अपने हाथ में रखेगी या फिर खुद से रिहा हुई पूर्व पीएम खालिदा जिया को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तमाम अटकलों और कयासों के बाद ये खोज नोबेल पुरस्कार विजेता 84 साल के अर्थशास्त्री पर जाकर खत्म हुई। मुहम्मद युनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मुहम्मद युनुस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अंतरिम मंत्रिमंडल के 16 अन्य सदस्य मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े लोग हैं और इसमें छात्र आंदोलन के दो नेता भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन छात्र नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों

और सेना के बीच हुई चर्चा के बाद किया गया। जैसे ही बांग्लादेश इस संक्रमणकालीन चरण में प्रवेश कर रहा है, अमेरिका हो या चीन, भारत हो या पाकिस्तान सभी की निगाहें मुहम्मद युनुस पर जा टिकी हैं कि वो जो भरोसा उन पर दिखाया गया है उस उम्मीद पर वो खड़े उतर पाते हैं या नहीं। युनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें सबसे गरीब लोगों का बैंकर भी कहा जाता है। पेशे से अर्थशास्त्री और बैंकर युनुस को गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रोक्रेडिट के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। युनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की ताकि उन उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराए जा सकें जो सामान्यतः उन्हें प्राप्त करने के योग्य नहीं होते। लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बैंक की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के लघु वित्त पोषण के प्रयासों को बढ़ावा दिया।

हसीना ने युनुस को विदेशी ताकतों की कटपुतली बताया। देश में जब भी कुछ गलत होता तो वे इसका इल्जाम युनुस पर लगातीं। एक बार हसीना ने युनुस को खून चूसने वाला 'कहा था। युनुस हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने हसीना के इस्तीफे को देश का दूसरा मुक्ति दिवस ??बताया है। युनुस को 2008 में हसीना सरकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ा जब उनके प्रशासन ने युनुस के खिलाफ कई



जांच शुरू कीं। युनुस ने पहले घोषणा की थी कि वह 2007 में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, हालांकि उन्होंने अपनी योजना पर अमल नहीं किया। उनकी सरकार ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक को 2011 में उन्हें ग्रामीण बैंक के एमडी पद से हटा दिया था। इस जनवरी में युनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए छह महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। जून में, उन्हें और 13 अन्य लोगों को एक अन्य मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसमें उनके द्वारा स्थापित एक दूरसंचार कंपनी के श्रमिकों के कल्याण कोष से 2 मिलियन डॉलर का गवन शामिल था।

2010 में, नॉर्वेजियन डॉक्यूमेंट्री में युनुस के ग्रामीण बैंक पर कर चोरी करने का आरोप लगाया गया था। 2011 में बांग्लादेश के सरकार-नियंत्रित केंद्रीय बैंक ने उन्हें ग्रामीण बैंक के प्रमुख के पद से हटा दिया, यह कहते

हुए कि उन्होंने 60 वर्ष की कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु पर कर ली है। युनुस कई कानूनी मामलों में उलझे रहे, जिनके बारे में उनका दावा था कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, युनुस पर हसीना सरकार द्वारा 190 से अधिक मामलों में आरोप लगाए गए हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। मोहम्मद युनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कालित बताते हैं। उनका कहना है कि हसीना भारत की शह पर तानाशाह बनीं और बांग्लादेश की सत्ता पर जबरदस्ती काबिज हुई।

बांग्लादेश में चाहे शेख हसीना रही हो चाहे जनआक्रोश में उपजी हिंसा और तख्तापलट के बाद अब मुहम्मद युनुस हो। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुस के हाथों में कुछ समय के लिए देश की बागडोर आने के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि भारत के साथ बांग्लादेश संबंध कैसे होंगे। क्या शेख हसीना की तरह बेहतर रहेंगे। या फिर इस पर चीन पाकिस्तान की काली छाया पड़ेगी। हालांकि जिस तरह मुहम्मद युनुस के समर्थन में जगल नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया खालिदा जिया धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात कर रही हैं। उससे लगता है

कि बांग्लादेश भटकाव का रास्ता इच्छियार नहीं करेगा। उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि हमें नया बांग्लादेश बनाना है। गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश बनाना है। ऐसा देश जहां किसी का शोषण न हो। इसके साथ ही उन्होंने छात्र और युवाओं को देश का भविष्य बताया है। युनुस भी इन बातों को समझते हैं। उन्होंने नई जिम्मेदारी की पेशकश स्वीकारने के बाद यह साफ कर दिया कि भारत से रिश्ते सुधारने के कई मौके मिलेंगे और यह उनकी प्राथमिकता में है। भारत भी हर मौके पर यह साफ करता रहा है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए भी वह न केवल उसके साथ विशिष्ट और करीबी रिश्ता कायम रखना चाहता है बल्कि विकास की उसकी यात्रा में योगदान भी जारी रखना चाहता है।

तख्तापलट के बाद बांग्लादेश कौन सा रास्ता अच्छियार करेगा भारत समेत पूरे दुनिया की निगाहे इस पर टिकी है। उम्मीद है मुहम्मद युनुस से जो कि खुद एक अर्थशास्त्री हैं। वो लोकतंत्र की राह पर चलते हुए वो विकास की अहमियत को समझते हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत के महत्व को भी बखूबी जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रोफेसर मुहम्मद युनुस को नई जिम्मेदारियों संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति,

## विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में छलांग का पथ किया था प्रशस्त

### कृष्ण प्रताप सिंह

आज की तारीख में हम जब भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की अगुआई में अपने देश को अंतरिक्ष में उंची छलांगें लगाते देखते हैं, गर्व से अपना सीना जरूर चौड़ा करते हैं। लेकिन क्या ऐसे अवसरों पर हमें इसरो की नींव की ईंट रहे अपने लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक स्मृतिशेष विक्रम अब्बालाल साराभाई की याद भी आती है? दरअसल, यह विक्रम ही थे, जिनकी कमान में 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को 15 अगस्त, 1969 को इसरो का रूप दिया गया। अनंतर उसके वैज्ञानिकों ने बेहद विपरीत परिस्थितियों में, कहना चाहिए उस 'बैलगाड़ियों के युग' में अपनी कड़ी मेहनत से अंतरिक्ष में हमारी छलांगों की आधारशिला रखी। फिर तो स्वाभाविक ही विक्रम 'भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह' कहलाए। इससे पहले 1963 में 21 नवंबर को केरल में तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा में देश का पहला राकेट लांच करके वे 'राकेट पिता' भी बन चुके थे। दुनिया के महान भौतिक विज्ञानियों में शुमार विक्रम अप्रतिम खगोलशास्त्री और उद्योगपति भी थे। इससे भी बड़ी बात यह कि वे जीवन भर प्रयासरत रहे कि विज्ञान के विभिन्न प्रयोग आम आदमी के काम आए और उसकी चेतना का विकास व विस्तार करें। वे चाहते थे कि अंतरिक्ष अभियानों में दुनिया के धनी देशों से अंधस्पर्धा से बचते हुए देश को उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में अग्रणी बनाकर उसकी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। 1975 में भारत ने एक रूसी कास्मोड्रोम से अपने आर्यभट्ट नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दुनिया को चिकित्त कर डाला तो उसे विक्रम की बनाई परियोजना की सफलता के रूप में ही देखा गया था। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 24 जनवरी, 1966 को हुई एक भीषण विमान दुर्घटना में अपने परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को गंवाकर देश टगा-सा रह गया था। उनके रहते हमारा परमाणु कार्यक्रम दुनिया की कई शक्तियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था, जिसके चलते उक्त विमान दुर्घटना को लेकर यह संदेह भी जताया गया कि कहीं उसके पीछे भाभा की हत्या का षड्यंत्र तो नहीं था। वे नहीं रहे तो यह सवाल बहुत बढ़ा हुआ था कि उनकी जगह किसे दी जाए जो उक्त कार्यक्रम को उनकी ही तरह समर्पित भाव से आगे बढ़ा सके। अंततः यह तलाश विक्रम साराभाई पर ही खत्म हुई और मई, 1966 में उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनका यह कार्यभार संभालना इस अर्थ में उनकी बहुत बड़ी देशसेवा सिद्ध हुआ कि जब तक वे रहे, भाभा का अभाव नहीं महसूस होने दिया। न ही यह स्थिति आने दी कि देश के परमाणु कार्यक्रम को अपने लक्ष्यों से समझौता करना पड़े।



## भीड़ के सामने जनतांत्रिक सत्ता और न्यायपालिका

### कमलेश पांडे

जनतांत्रिक देश बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ, वह लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। यह उसकी अविश्वसनीयता की एक बानगी है, जिससे किसी भी लोकतांत्रिक देश में अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। सवाल है कि जनता यदि बगावत पर उतर जाए या उसके नाम पर हिंसक प्रवृत्ति के लोग गोलबंद होकर सड़कों पर उतर जाएं तो संविधान और संविधान का शासन कुछ भी मानने नहीं रखता है। यह स्थिति विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

यू तो किसी भी लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि विदेशी ताकतों की सरपरस्ती में विपक्ष अपने ही देश और देशवासियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चलाए और फिर सत्ता तक पहुंच जाए। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न आधा दर्जन से अधिक देशों में यह प्रचलन बढ़ा है, जो सर्वाधिक चिंता की बात है। जानकार बताते हैं कि संभवतया इसी स्थिति से बचने के लिए विधायिका के बीच से कार्यपालिका के कड़ावर चेहरे से युक्त निष्पक्ष प्रशासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और उन्मुक्त प्रेस की परिकल्पना की गई। लेकिन बांग्लादेश में पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनीं अवामी लीग नेत्री शेख हसीना की सरकार का जिस तरीके से तख्तापलट कराया गया, उससे निर्वाचित सरकारों और वैश्विक लोकतंत्र दोनों के सामने एक आसन्न खतरा मंडाने लगा है। वहीं, बदलती स्थिति से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की धूलधूसरित हुई है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटीोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि वह नरसीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ हैं। उन्होंने हिंसा को खत्म करने की अपील भी की। कभी पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने



वाले बांग्लादेश के लिये सैन्य तख्तापलट कोई नई बात नहीं है। हां, दुनिया के सबसे बड़े और सफल लोकतांत्रिक देश भारत की छत्रछाया में पले-बढ़े बांग्लादेश के लिए यह गम्भीर चिंता का विषय जरूर है। मसलन, बांग्लादेश की मुक्ति संघर्ष वाहिनी के अंग रहे लोगों के वंशजों को 30 प्रतिशत या उससे अधिक आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले पर आप एक सकारात्मक न्यायादेश के बाद वहां भड़का छात्र आंदोलन कब इस्लामिक चरमपंथियों के जिहाद में तब्दील हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चल सका। हाँ, भारत समेत दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों की आंखें तब खुलीं, जब वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अवामी लीग पार्टी का समर्थक करार देकर उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। जगह-जगह उनकी हत्या की जाने लगी और उनके घर-मंदिर में लूटपाट मचाने व तोड़फोड़ करने के बाद उसे फूंक दिए जाने की घटनाएं बढ़ने लगीं। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से भागकर भारत आईं और यहां शरण लीं। फिर तो यह स्पष्ट होते देर न लगी कि उग्र छात्र आंदोलन की आड़ में इकट्ठा हुए इस्लामिक चरमपंथियों की हिंसक भीड़ के सामने लोकतांत्रिक सत्ता और न्यायपालिका समेत पुलिस, सेना व संविधान की औकात कितनी क्षणभंगुर है।

गोया, इसके दृष्टिगत अपनाई गई सैन्य तटस्थता भी कोई शुभ संकेत नहीं है। यह सही है कि सेना ने शेख हसीना को सुरक्षित भारत जाना दिया। फिर संसद भंग करके एक नोबेल

पुरस्कार विजेता के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन कराया दिया। फिर छात्र धमकियों के मद्देनजर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन को इस्तीफा देना पड़ा। अब वहां देर-सबेर चुनाव होंगे और फिर नवनिर्वाचित सरकार सैन्य प्रमुख के साथ क्या व्यवहार करेगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लिहाजा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के गूढ़ मायने को समझना होगा।

सवाल है कि क्या सेना, पुलिस, सरकार या न्यायालय आदि उग्र छात्र आंदोलनकारियों की खाल में छिपे उन अराजक तत्वों के इशारे पर थिरकेगी, जो सरिया कानून के हिमायती हैं, आतंकवादियों-उग्रावादियों और अंडरवर्ल्ड के पृष्ठपोषक हैं? या फिर विधि के शासन से चलेगी, जिसके लिए पुलिस, सेना, सिविल प्रशासन, न्यायालय के साथ-साथ पूरी सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। लोकतांत्रिक सत्ता हमेशा चुनाव से बदलनी चाहिए, न कि सैन्य तख्ता पलट और सरिया कानून के हिमायती जमात के हिंसक आंदोलनों से! लेकिन जिस तरह से कभी अफगानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकारें गिराई गईं और लोकतंत्र के पहरूए पश्चिमी देशों समेत भारत ने चरमपंथियों के खिलाफ नरमी दिखाई, वह इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। न्यू वर्ल्ड आर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था के पैरोकार पहले चरमपंथियों को हवा देकर लोकतांत्रिक विफलता का माहौल पैदा करेंगे और उनके दमन के नाम पर अपना पूंजीवादी फैलापूरी और आम आदमी को डंसना शुरू कर देंगे। आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र का शोर मचा हुआ है। जहां भी और जो भी इसे चुनौती देता है, उसके खिलाफ पश्चिमी देश लामबंद हो जाते हैं। दुनिया के कई देशों में हुए सैन्य तख्तापलट के तुरन्त बाद नवनिर्वाचित सरकार का गठन करवाया गया। आज पूंजीवादी अमेरिका और उसके मित्र देश साम्यवादी रूस और चीन का विरोध इसलिए भी करते आये हैं कि वहां सीमित या नियंत्रित लोकतंत्र है।

## बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा पर चुप्पी उचित नहीं

### दीपक कुमार त्वागी

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों के विरोध में हाल ही में राजधानी ढाका, चटगांव, कुरीग्राम, ठाकुरगांव, छत्रग्राम, दिनाजपुर, बरिशाल, मेमेन्सिंध, तंगेल, नीलाफामारी आदि शहरों में लाखों की संख्या में हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शन करके सरकार से तत्काल कट्टरपंथियों के हमलों को रोकने की मांग करते हुए, नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए, दंगाईयों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए, पूरे विश्व समुदाय का ध्यान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले पर आकर्षित करने का कार्य किया है। वैसे भी बांग्लादेश में हिंसा व तनाव के चलते ही म्यांगार की सीमा पर शरण लेने की उम्मीद से खड़े बांग्लादेशी लोगों के साथ घटित हुई बेहद हृदयविदारक घटना को अभी हाल ही में पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। वहीं भारत की बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर भी इसी तरह से लाखों की संख्या में जगह-जगह बांग्लादेशी हिन्दू भारत में शरण लेने की उम्मीद से निरंतर खड़े हुए हैं। वहीं भारत में धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित ठेकेदार अभी तक भी इस ज्वलंत मसले पर कुंभकर्णी नौद में सोए हुए हैं, जबकि इनमें से बहुत सारे लोग मानवाधिकार के नाम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, लिबिया, गाजा पट्टी आदि तक के आतंकियों के हक में भी खुलेआम भारत की सड़कों पर उतर करके हंगामा बरपाने से बाजु नहीं आते। लेकिन आज बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों पर यह लोग चुपचाप तमाशाबीन बनकर बैठे हुए हैं, अब इन लोगों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं का दर्द, इंसानियत का सरेआम होता कल्लेआम व मानवाधिकार का उल्लंघन होते हुए नज़्द नहीं आ रहा है।

बांग्लादेश में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर के कुछ माह से छात्रों के द्वारा सड़कों पर जबरदस्त हंगामा बरपाया हुआ था। जिस हिंसक हंगामे की आड़ में ही बांग्लादेश में जनवरी 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेख हसीना सरकार का 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वहां के हालात को देखकर लगता है कि आरक्षण का मुद्दा तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो कट्टरपंथियों का शेख



हसीना को सत्ता से हटाकर के बिना चुनाव जीते सरकार पर कब्जा जमाना था, जिस मकसद में वह सफल भी हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट करने के लिए ही कट्टरपंथी षड्यंत्रकारियों के द्वारा पूरे बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक कर आम लोगों का कल्लेआम करवा दिया गया। हिंसा का आलम यह था कि खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे, वह भी जैसे-तैसे करके बांग्लादेश को छोड़कर के भारत सुरक्षित पहुंच पाई हैं। लेकिन शेख हसीना के विरोध के नाम पर चल रहे इस पूरे हिंसक आंदोलन को हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद तो पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आज भी बांग्लादेश में हिंसा व हंगामे का जबरदस्त दौर जारी है, वहां पर कट्टरपंथी दंगाईयों के दबाव व भय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक को भी अपना पद छोड़ना पड़ा है। इस परिस्थिति में सोचने वाली बात यह है कि 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बाहुल्य बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी तकरीबन आठ प्रतिशत 1.35 करोड़ के लगभग है, वहीं इस अधिकांश हिन्दू आबादी को परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कट्टर समर्थक माना जाता है। लेकिन शेख हसीना से बांग्लादेश की सत्ता को हथियाने के इस षड्यंत्र में अवामी लीग पार्टी के नेताओं व समर्थकों का जान-माल दंगाइयों के निशाने पर शुरूआत से ही रहा है। जिसके चलते अब यह दंगाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के जान-माल को निशाना बना रहे हैं। जिसके बाद वहां के अल्पसंख्यकों के विभिन्न संगठन प्रदर्शन करके व अंतरिम सरकार को खुला पत्र लिखकर के सुरक्षा मांग रहे हैं। इन संगठनों के अनुसार बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 में हिन्दुओं को बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी दंगाईयों के द्वारा

निशाना बनाया गया? है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी वहां अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बने हुए अमानवीय क़रूरतपूर्ण हालात से बुरी तरह से भयभीत हैं, वह अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर के बेहद डरे हुए हैं। जिसकी वजह से ही हम सभी संगठन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद युनुस से तत्काल उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देने की मांग करते हुए कट्टरपंथी दंगाईयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा तथाकथित आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर के वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जबरन सत्ता से हटाने के बाद से ही पूरे देश में कानून-व्यवस्था के हालात दिन-प्रतिदिन बेहद बदतर होते जा रहे हैं। अब तो पूरे देश में पुलिस तोड़फोड़ व हिंसा को केवल तमाशाबीन बनकर देख रही है। दंगाईयों के द्वारा जगह-जगह सार्वजनिक व निजी संपत्ति में तोड़फोड़ करना, लूट-पाट करना, आगजनी करना, अपहरण करना, सरेआम हत्या करना, बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं को अंजाम देना आम बात हो गयी है। लेकिन अब विचारणीय तथ्य यह है कि तख्तापलट के इस षड्यंत्रकारी खेल में मुस्लिम बाहुल्य देश में अल्पसंख्यक समुदाय के 1.35 करोड़ हिन्दुओं को जानबूझकर के क्यों निशाना बनाया जा रहा है, हिन्दुओं के अवास दुकान, मंदिर, उधोग-धंधे आदि वहां के बहुसंख्यक दंगाईयों के निशाने पर क्यों आये हुए हैं, आखिर वह किसके संरक्षण पर हिन्दुओं को बेखौफ होकर के नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों बांग्लादेश के आम लोग, राजनेता, पुलिस, प्रशासन व सेना आदि सब तमाशाबीन बन करके चुपचाप खड़े होकर के कल्लेआम का यह तमाशा देख रहे हैं। इस हालात में अहम विचारणीय तथ्य यह भी है कि ना जाने बांग्लादेश का सिस्टम किस दबाव में आकर के इस तरह के कट्टरपंथी दंगाईयों की छलियों को गोलियों से छलनी करने से बच रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि बिना चुनाव जीते सत्ता हथियाने की इस जंग के मुद्दे की आड़ में हिन्दुओं के जान-माल को जबरदस्त ढंग से पहले दिना से ही हानि क्यों पहुंचायी जा रही है। धरातल पर बन रहे हालातों को देखकर लगता है कि यह स्थिति बांग्लादेश में रहने वाले हिन्दू अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सोचा-समझा षड्यंत्र है।

## चीन के कितने चेहरे, जानते हैं आप?

### मृत्युंजय राय

चीन के आर्थिक मॉडल और उसकी कामयाबी को अक्सर चर्चा होती है। किस तरह से चीन ने 'मिरेकल इकॉनमी' का दर्जा हासिल किया और कैसे वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने पूंजीवाद का एक अलग ही रास्ता दुनिया को दिखाया। कई देशों ने इसकी नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन चीन जैसी तर्कही कोई और मुल्क हासिल नहीं कर पाया। यहां तक कि हमारे यहां भी यह चर्चा आज तक होती आई है कि क्या भारत इस मॉडल को अपनाकर मैन्यूफैक्चरिंग में बड़ी ताकत नहीं बन सकता ताकि कृषि क्षेत्र से अधिक कामगारों की खपत वाले उद्योग धंधों की ओर लोगों को शिफ्ट किया जा सके और बेरोजगारी में कमी लाई जाए। इस बारे में जानकार दो धड़ों में बंटे हुए हैं। कुछ इसके पक्ष में तो कुछ विरोध में। चीन फिलहाल आर्थिक दुश्धारियों से गुजर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास, भूगोल और विरासत के जरिये भी इस देश को समझा जा सकता है। इस नजरिये से देखने पर चीन की कैसी तस्वीर सामने आती है? At The Edge of Empire: A FamilyOs Reckoning with China में एडवर्ड वोंग (Edward Wong) ने यही कोशिश की है। यह किताब संस्मरण है, जिसके जरिये लेखक ने चीन के अंदर निहित विरोधाभासों को सामने लाने का प्रयास किया है। एडवर्ड इसमें अपने पिता और चाचा के बारे में लिखते हैं। दोनों का जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हॉंगकॉंग में हुआ था। एडवर्ड के पिता और चाचा का बचपन कुछ समय तक दक्षिण चीन में भी गुजरा था। 1948 में उनके चाचा अमेरिका पढ़ाई के लिए चले गए और पिता 1950 में पेरिचिंग। उनके पिता वहां क्रांति के सिपाही बनने गए थे। कुछ समय बाद उन्हें पार्टी ने शिंगच्यांग में तैनात किया। क्रांति के इस सिपाही का क्यों माओवाद से मोहभंग हुआ, इस बारे में एडवर्ड अपनी किताब में लिखते हैं। वह बताते हैं कि जब उनके पिता ने बाद के वर्षों में देखा कि क्रांति के कई नायकों की हत्या कर दी गई और माओ की 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' पॉलिसी की वजह से चीन को कैसे भूखमरी से गुजरना पड़ा तो उन्हें इसके खोखलेपन का अहसास हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत माओवादी चीन ने औद्योगिक ब्रिटेन की बराबरी करने का लक्ष्य तय किया था। एडवर्ड के पिता ने यह सब देखकर चीन से भागने का फैसला किया। वह पहले तो हॉंगकॉंग गए, जहां उस वक्त ब्रिटेन की हुकुमत चरती थी और लोकतंत्र था। अफ्रीम युद्ध में हार के बाद हुए समझौते की वजह से हॉंगकॉंग को 100 वर्षों के लिए चीन ने ब्रिटेन को लीज पर दिया था। खैर, एडवर्ड के पिता हॉंगकॉंग में भी ज्यादा वक्त नहीं रुके और 1962 में अमेरिका पहुंचे। कोई एक दशक बाद यहीं एडवर्ड का जन्म हुआ। एडवर्ड की वापसी चीन में 2008 में हुई। वह एक अमेरिकी अखबार के संवाददाता के रूप में चीन पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने परिवार के इतिहास का पता लगाया। वह अपने पिता के गांव गए। यहां उन्होंने देखा कि किस तरह से कम्युनिज्म के पारिवारिक रिश्तों के बारे में विचार आज तक समाज पर प्रभाव रखते हैं। उन्होंने इसकी कमियां भी देखीं। ये विचार चीन में Individualism में बाधा बनते हैं, जबकि अमेरिका में एडवर्ड के परिवार ने इसी Individualism की बदीलत तरक्की हासिल की थी। वह शिनच्यांग, तिब्बत और हॉंगकॉंग भी गए, जहां उनके पिता रह चुके थे। इन जगहों पर जाकर उन्होंने देखा कि किस तरह से अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और औपनिवेशिक इतिहास के कारण लोगों में कम्युनिस्ट सत्ता को लेकर नाराजगी है और सरकार कैसे इसे दबाने की कोशिश करती रहती है। अपने परिवार के किस्सों के जरिये एडवर्ड चीन की तस्वीर रखने में कामयाब रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने चीन के अतिविरोधों को भी सामने रखा है।



### यूपी उपचुनाव के लिए मायावती ने ठेकी ताल

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रिमो मायावती ने घोषणा की कि उनकी पार्टी सभी दस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक का ब्यौरा एक्स पर साझा किया, जिसमें सभी दस निर्वाचन क्षेत्रों में बसपा के उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि फूलपुर और मंझवा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। मायावती के इस ऐलान से भाजपा और सपा की टेंशन बढ़ सकती है। बैठक के दौरान मायावती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया और उन पर विभाजनकारी बुलडोजर राजनीति का इस्तेमाल करने और महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने मस्जिदों, मंदिरों और वक्फ संपत्तियों के संचालन में सरकार के हस्तक्षेप की भी निंदा की।



### फिर से ईडी के निशाने पर राहुल, पूछताछ के आसार

**नई दिल्ली।** लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि संघीय एजेंसी कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों के हवाले से, रायबरेली के सांसद को पार्टी द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिए जल्द ही बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी को राहुल से नए दौर की पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच पूरी करना चाहती है, जिसमें उसने पहले ही 751 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। कांग्रेस नेता से इससे पहले जून 2022 में प्रवर्तन एजेंसी ने चार बैठकों में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की थी।



### केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जिससे पता चलता है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल से कहा था कि वे नियमित जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दे दी थी।



### के. कविता की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई

**नई दिल्ली।** भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें, कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि बीआरएस नेता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (अब रह कर दी गई) को बनाने और उसे लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 अगस्त की वाद सूची के मुताबिक, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।



### फारूक अब्दुल्ला का सुरक्षाबलों पर गंभीर आरोप

**श्रीनगर।** जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से बवाल खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में हो रहे चुपसैठ के लिए आतंकियों और सुरक्षाबलों को कथित मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है। अब्दुल्ला के इस बयान पर पुलिस महानिदेशक आरआर स्वेन ने आपत्ति जताई है। भाजपा ने भी फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर पलटवार किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सीमाओं पर बहुत बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। इसके बाद भी आतंकी भारत में चुपसैठ करते हैं। हमारी बर्बादी के लिए सब मिले हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के अंततनाग में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमारे दो जवान शहीद हो गए थे जबकि दो आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आरआर स्वेन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान को बेहद अपमानजनक है।



## लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे मोदी

### विकसित भारत का पेश कर सकते हैं रोडमैप

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शकों के सामने रखेंगे और भारत को विकसित देश बनाने का रोडमैप पेश करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के विशेष अतिथियों को प्रतिष्ठित लाल किले पर भव्य समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप, चारों समूहों के प्रतिनिधि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।



15 अगस्त को होने वाले समारोह में इन समूहों से करीब 4,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इन मेहमानों को 11 श्रेणियों में बांटा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण, युवा मामले और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को क्रमशः किसानों, युवाओं और महिलाओं को आमंत्रित करने

की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, शिक्षा और रक्षा मंत्रालयों ने भी मेहमानों की सूची तैयार कर ली है। नीति आयोग ने भी मेहमानों को आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया कि पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में 18,000 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे।

दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत 13 अगस्त को होने वाली 'फुल ड्रेस रिहर्सल' के लिए बंद की जाने वाली सड़कों और वैकल्पिक मार्गों के संबंध में एक परामर्श जारी

किया है। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसकी लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड यह आठ मोटरमार्ग मंगलवार तड़के चार बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक बंद रहेंगे।

परामर्श में कहा गया है कि अभ्यास के लिए बिना पार्किंग 'लेबल' वाले वाहनों को सी-हेक्लान, इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खता और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड तथा निजामुद्दीन खता से सलीमागढ़ बाईपास होने हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक बाहरी रिंग रोड पर इन मार्गों में प्रवेश करने से बचना चाहिए।

## हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को ये देश में आर्थिक अराजकता की हो रही साजिश

**नई दिल्ली।** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ अमेरिका की शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है।



इन सब के बीच भाजपा की ओर से आज पलटवार किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर एक संवाददाता सम्मेलन किया और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए। प्रसाद ने कहा कि तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस पार्टी, ईडी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले दल कितने लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं।

भाजपा नेता ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अपनी जांच पूरी करने के बाद रश्मिद्रु ने हिंडनबर्ग के खिलाफ जुलाई में एक नोटिस दिया था। अपने बचाव में जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट पेश की है, जो पूरी तरह आधारहीन है। उन्होंने कहा कि भारत की

जनात द्वारा टुकड़ाए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है?

उन्होंने कहा कि भारत शेरों के मामले में भी सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। बाजार को सुचारू रूप से चलाना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। प्रसाद ने कहा कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच पूरी करने के बाद जब सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ नोटिस जारी किया, तो अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना ही उन्होंने यह हमला किया, यह एक बेबुनियाद हमला है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस ने निवेश किया है, जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोगेमेंड चलाने हैं और मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं। टूलकिट वालों को भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है?

## ममता बनर्जी का पुलिस को अल्टीमेटम

### बोली- रविवार तक आरोपी न पकड़े तो सीबीआई को सौंपें केस

**कोलकाता।** कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम केस को सीबीआई को सौंप देंगे।



सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला, तो मैंने उनको तत्काल और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अस्पताल में नर्स थीं, सुरक्षा कर्मी थे तो यह घटना कैसे हुई। पुलिस ने मुझे

बताया है कि अस्पताल के अंदर कोई था। उन्होंने कहा कि मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। पुलिस, डॉंग स्कवाड, फॉरेंसिक विभाग और अन्य टीमों काम पर लगी हुई हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस रविवार तक मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है। ऐसा न हुआ तो हम इस केस को अपने हाथ में नहीं रखेंगे। हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे।

वहीं डीसीपी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता का कहना है कि अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों के नाम अब एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। कोई भी अवांछित व्यक्ति अस्पताल में प्रवेश नहीं करेगा। डॉक्टरों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अस्पताल के चारों ओर गार्डों को

## बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार पर अखिलेश का पोस्ट

**लखनऊ।** बांग्लादेश में उठापटक के बीच हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। यह कही ना कही भारत की चिंता को बढ़ाने वाली है। इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट तिया है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई भी समुदाय चाहे वह बांग्लादेश का अलग नज्दियेवाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म-पंथ-मान्यता माननेवाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए।

सपा प्रमुख ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। वहीं, कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस एक 'धर्मनिरपेक्ष' नेता हैं और वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके देश में विभिन्न समुदायों के बीच कोई टकराव नहीं हो। पवार ने पुणे में पत्रकारों से कहा, 'मेरी जानकारी के अनुसार, वह (युनुस) धर्मनिरपेक्ष हैं और वह विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न भाषाई समूहों के बीच टकराव पैदा करने का काम कभी नहीं करेंगे।

## स्टील प्रमुख समाचार

### भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड टीम का ऐलान

**नई दिल्ली।** न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान टीम



के बीच 9-13 सितंबर तक टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम को भारत का दौरा करना है, जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है। टिम साउदी की कप्तानी में 15 सदस्यीय कीवी टीम अफगान टीम के खिलाफ खेलेगी। इस टीम में 18 महाने बाद माइकल ब्रेसवेल को वापसी हो रही है।

न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 9 से 13 सितंबर के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा सोमवार को की। अफगानिस्तान टीम भारत में न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा। इस एक मात्र टेस्ट मैच के लिए नोएड के स्टेडियम को तैयार किया जा चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेलने के बाद न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। यहां उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत दो टेस्ट मैच खेलना है।

वहीं इस टेस्ट टीम में 18 महाने बाद माइकल ब्रेसवेल को वापसी हुई है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत में खेले जाने वाले मुकाबले में मिचेल सैंटनर, एजाज पेटल और रचिन रविंद्र के साथ ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल को शामिल किया गया है। कीवी कप्तान टिम साउदी के पास ग्लेन फिलिप्स के रूप में पांचवां स्पिन विकल्प भी होगा।

### अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम

टिम साउदी (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, केन विलियमसन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, टॉम लेथम, डेरिल मिचेल, विल ओउडके, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, बैन सीयर्स, विल यंग।

## आर्थिक/वाणिज्य/वित्त/प्रमुख समाचार

### सैंसेक्स-निफ्टी फ्लैट नोट पर बंद

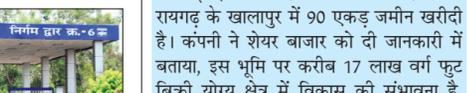
**नई दिल्ली।** हिंडनबर्ग-सेबी विवाद के बीच शुरूआती गिरावट से उबरते हुए आज यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट नोट पर बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 56.99 अंक या 0.07 प्रतिशत टूटकर 79,648.92 पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में इंडेक्स 479.78 अंक या 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,226.13 के निचले स्तर पर आ गया था। बाद में बेंचमार्क में तेज सुधार हुआ और यह 400.27 अंक या 0.50 प्रतिशत चढ़कर 80,106.18 पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 20.50 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 24,347.00 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,212.10 और 24,472.80 के रेंज में कारोबार हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 शेयर हरे निशान में बंद हुए। एक्सिस बैंक, इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

## हिंडनबर्ग के हमलों के बाद अदाणी के शेयर 17% तक टूटे

**नई दिल्ली।** अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदाणी प्रकरण में सीधे सेबी के चेरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल पुरी पर आरोप लगाने के बाद अदाणी समूह के शेयरों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शुरूआती कारोबार में अदाणी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर 17% तक गिर गए। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 53000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस बिकवाली से अदाणी समूह के 10 शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप घटकर 16.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, यह बिकवाली ज्यादा देर नहीं चली और धीरे-धीरे खरीदार लौटने लगे, जिससे प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर लौट गए। बीएसई सेंसेक्स पर सूचीबद्ध अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 17 प्रतिशत, अदाणी टेलेंट गैस में 13.39 प्रतिशत, एनडीटीवी में 11 प्रतिशत और अदाणी पावर में 10.94 प्रतिशत की गिरावट आई।

## भेल को ताप विद्युत परियोजना का ठेका मिला

**नई दिल्ली।** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल



को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से 1,600 मेगावाट की परियोजना का ठेका मिला है। भेल ने बयान में कहा, इस 1600 मेगावाट कोडरमा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के जरिये हासिल किया गया। कोयला आधारित इकाई झारखंड के कोडरमा जिले में ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण) आधार पर स्थापित की जाएगी। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग व विनिर्माण कंपनियों में से एक है।

## सिर्फ जीडीपी काफी नहीं, जीईपी को साथ लेकर चलने से बनेगी बात

### वीर सिंह

वैश्व के लगभग सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मानकों से आंकते हैं। भूदान सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस) को अपना सबसे बड़ा आधार मानता है। लेकिन 19 जुलाई को उत्तराखंड ने अपनी अर्थव्यवस्था के आकलन के लिए जिस मानक की घोषणा की, वह अद्वितीय है। सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) को अपनी अर्थव्यवस्था का मानक मानने वाला यह हिमालयी राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है, जो दुनिया भर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। हालांकि ऐसी आर्थिक विकास की नीति कोस्टारिका तथा कुछ अन्य देशों में आंशिक रूप से प्रभावी है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से प्रयासरत पर्यावरणविद डॉ अनिल जोशी और



उत्तराखंड प्रशासन की यह पहल स्वागत योग्य है, परंतु इस पर इतनी चर्चा नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए। जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक रूप से स्वीकृत माप है, परंतु आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी पर्यावरणीय लागतों और लाभों को ध्यान में रखते हुए यह आर्थिकी के वास्तविक आकलन की एक कमजोर कड़ी है। जबकि सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) की अवधारणा मानव सहित सभी जीवों के कल्याण और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के योगदान को मापने के सार्थक दृष्टिकोण के रूप में उभरी है। महात्मा गांधी ने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, न कि लालच की पूर्ति करने वाली, आर्थिकी का दर्शन दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने पारिस्थितिकी ही स्थायी आर्थिकी है का सिद्धांत दिया था।

के साथ पूर्ण राजनीतिक निष्ठा से जीईपी को अपनाते से सतत राष्ट्रीय विकास प्रथाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है। यह बदलाव अधिक संतुलित और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों को जन्म दे सकता है, जो आर्थिक विकास का तालमेल पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ बनाए रखती है। वैसे जीईपी की अवधारणा भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के अनुरूप भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इसकी गणना में कई चरण और पद्धतियां समाहित हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की जटिलता और विविधता को दर्शाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख दृष्टिकोण हैं - बाजार-आधारित मूल्यांकन, प्रतिस्थापन लागत विधि, आकस्मिक मूल्यांकन और लाभ अंतरण। जीईपी का उद्देश्य एक ही है-पारिस्थितिकी-केंद्रित सतत सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास। उत्तराखंड में जो जीईपी लागू किया जाना है, उसमें पर्यावरण के चार घटकों (जल, वायु, वन और मिट्टी) संबंधी सूचकांक शामिल हैं। आर्थिक विकास की नीतियों, योजनाओं और प्रक्रियाओं में पर्यावरण के इन घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित रखना किसी भी प्रशासन का नैतिक दायित्व है और इसे मूर्त रूप देने में उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण-नैतिकता के प्रदर्शन का साहस दिखाया है। जीईपी को कार्रवाई योग्य नीतियों और निर्णयों में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है। सरकारों और संगठनों को अपनी योजना प्रक्रियाओं में जीईपी को एकीकृत करने और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक प्रोत्साहन में तालमेल बनाना चाहिए। उत्तराखंड में एक जीईपी सेल की स्थापना की बात कही गई है, जो जीईपी के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

# ई-ऑक्शन प्रणाली से काष्ठ के नीलामी में आणी प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता

मुख्यमंत्री साय और केन्द्रीय मंत्री यादव ने किया शुभारंभ नवा रायपुर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम 'दण्डकारण्य' लोकार्पित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज यहां नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग द्वारा दो करोड़ रूपए की लागत से तैयार किए गए अत्याधुनिक ऑडिटोरियम 'दण्डकारण्य' का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री केशव कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक गजेन्द्र यादव और केन्द्रीय वन महानिदेशक एवं भारत सरकार के विशेष सचिव जितेन्द्र कुमार भी शामिल हुए। ई-ऑक्शन प्रणाली से वन विभाग के विभिन्न काष्ठगारों में काष्ठ के नीलामी में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता आएगी। ई-ऑक्शन



की प्रक्रिया में ईओआई के माध्यम से एमएसटीसी के द्वारा ई-ऑक्शन कार्य किया जा सकेगा। काष्ठगार की काष्ठ नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से कराये जाने से शासन एवं बोलीदाता के लिए भुगतान की प्रक्रिया त्वरित एवं पारदर्शी हो जायेगी। इससे राज्य शासन के

राजस्व की वृद्धि होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग के विभिन्न काष्ठगारों में ईमरती काष्ठ, बहली, व्यापारिक बांस, जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती है। राज्य में 27 विक्रय डिपो संचालित किए जा रहे हैं। अभी अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया में कागजी

कार्यवाही तथा बहुत सारे रिकार्ड रखे जा रहे थे, अब ई-ऑक्शन प्रणाली के शुभारंभ हो जाने से कागजी कार्रवाई से निजात मिलेगी। दो करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ऑडिटोरियम- वन विभाग द्वारा करीब दो करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित इस

अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में अतिरिक्त साज-सज्जा, लाइट, साउंड सिस्टम, वातानुकूलित, स्टेज, एल.ई.डी स्क्रीन जैसी सुविधाओं के साथ 140 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वन मुख्यालय में समय-समय पर होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप, मैदान अमले, संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसके शुभारंभ हो जाने से वन विभाग द्वारा अब मुख्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एक 'स्टेट ऑफ आर्ट सभागार' में किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में प्रधान वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक श्री सुधीर कुमार अग्रवाल सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

## मेरी बात

गिरिश पंकज

### मानस पढ़ो बनो तुम ज्ञानी..

कल 11 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जी की 527 वीं जयंती थी. उनकी महान रचना रामचरित मानस को पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं. बचपन में पिताजी ने मानस पढ़ने के लिए दिया था। उसका नियमित पारायण हम लोग करते थे। राम मंदिर में जाते तो वहां किष्किंधा कांड और सुंदरकांड आदि भी नियमित पढ़ने का अभ्यास चलता। इसी का सुपरिणाम यह हुआ कि किष्किंधा कांड की बहुत सारी चौपाइयां याद हो गईं। रामचरितमानस की अनेक चौपाइयां, दोहे सहजता के साथ कंठस्थ हो गए। उसका लाभ यह हुआ कि मेरे लेखन में भी रामचरितमानस की चरणधूलि आती रही। और आज भी जब कभी मन अशांत होता है और कुछ अनुसंधान करने की इच्छा होती है, तो रामचरितमानस को पढ़ने लगता हूँ। तुलसीदास की चौपाइयों और दोहों से गुजरते हुए खुद को अनायास ही पुनरन्वेषण करने लगता हूँ। बड़े होने के बाद रामचरित मानस को कभी मैंने एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ा, ज्ञानार्जन के निमित्त ही पढ़ा। अब भी पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग पढ़ते हैं। अनेक घरों में अखंड रामायण पाठ भी होता है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग मंत्रमुग्ध होकर मानस का पाठ करते हैं। संगीतबद्ध पाठ भी करते हैं। फिल्मों धुनों में चौपाइयां तक गाते हैं, जिसे सुनकर श्रोता सिर हिला-हिला कर मग्न हो जाते हैं। लेकिन मैं इस तरह की भक्ति से परे होकर एक विशुद्ध साहित्यिक विद्यार्थी के रूप में अकसर मानस को पढ़ता हूँ। बालकांड को बड़े मनोयोग से पढ़ता रहा हूँ और हतप्रभ हो जाता हूँ कि कैसे महाकवि तुलसीदास जी ने इतने विशाल ग्रंथ की रचना सहज भक्ति-भावना के साथ कर दी। इतना महान काव्य ग्रंथ रच कर भी तुलसी कहते हैं, "कबित बिबेक एक नहीं मोरे /सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे"। बालकांड में उन्होंने काव्य-विमर्श भी जबरदस्त किया है। कविता कैसी हीनी चाहिए, कवि को कैसा होना चाहिए, इस पर वे विस्तार से प्रकाश डालते हैं। मानस रामजी की महान कथा है, जिसे तुलसीदास ने सहज सरल शब्दों में प्रस्तुत किया मगर उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ यह स्वीकार किया कि यह मेरी अपनी कृति नहीं है। यह तो वाल्मीकि रामायण और नाना पुराण आदि पढ़कर जो कुछ नवनीत निकला, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उन्होंने यह भी कहा कि "कवि न होऊँ नहिं चतुर कहावऊँ / मति अनुरूप राम गुण गावउँ। कह रघुपति के चरित अपारा/ कहँ मति मोरि निरत संसारा"। अर्थ कठिन नहीं है कि न तो मैं कवि हूँ और न अपने आप को चतुर कहलाता हूँ। मेरी अपनी जैसी बुद्धि है, उसके अनुरूप मैं रामजी के गुण गा रहा हूँ। कहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहां संसार में आसक मेरी बुद्धि। यह महाकवि तुलसीदास जी की अद्भुत उदारता है। उन्होंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर दी जो सीधे पूजा घर की पूजनीय वस्तु बन गया। तुलसीदास जी ने बालकाण्ड में सज्जनों की वंदना की और गुरुजनों को भी वंदना की। तथाकथित ज्ञानियों की भी वंदना की। साधुओं की वंदना की। श्रेष्ठ कवियों को याद किया। चौपाई इस तरह है 'जे प्राकृत कवि परम सयाने/ भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भए जे अहर्हो जे होइहिआगे / प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागे'। तुलसीदास जी कहते हैं जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं। जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान हैं और जो आज भी होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। इस तरह कपट-कदम पर तुलसीदास जी ने विनम्रता के साथ यह स्वीकार किया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह तो प्रभु की कृपा से मानस की रचना हो गई। तुलसीदास जी यह भी जानते थे कि श्रद्धाहीन लोगों को यह ग्रंथ पसंद नहीं आएगा इसलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में यह दोहा रचा, "जे श्रद्धा संकल रहित नहीं संतन कर साध/ तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ"। और यह भी कहा कि जो बेमन के साथ इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ते साथ ही नींद आने लगेगी "जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई /जातहिं नीद जुड़ाई होई"। इस तरह जब तक श्रद्धा ना हो रामचरितमानस में रुचि जाग्रत नहीं होगी। और मूर्ख लोग बिना पढ़े ही इसकी निंदा करते रहेंगे। मगर जिनमें एक बार मानस से अपना रिश्ता गंठ लिया, वह तो इसकी एक-एक चौपाई पढ़कर अपने भग्य को सराहेगा। मानस को पढ़कर मुझे यही अनुभूति हर बार होती रही। और अंत में...मानस- गुणगान करते हुए दस चौपाइयां बनीं, वह यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ।



रायपुर। भाजपा की तिरंगा यात्राओं ने छत्तीसगढ़ के माहौल को पूरी तरह देशभक्तिमय कर दिया है, छत्तीसगढ़ भारत माता की जय के जयघोष और नारों से लोगों में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को लेकर उत्साह का संचार हो रहा है। भाजपा तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव ने जगदलपुर के तिरंगा चौक में संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ की। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं क्षेत्रीय जेन उपस्थित रहे इस दौरान श्री देव ने इस अभियान के तहत अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम हर घर तिरंगा यात्रा में मंसनावल दुर्गा मंदिर से बरवाही चौक तक,

विकासखंड रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर रामनुजगंज में शामिल हुए। जनपद पंचायत खड्गवाँ में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री श्याम बिहारी जयसवाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक से अपने घरों व प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने की अपील की। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कुरुद में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मंडलों में निकली तिरंगा यात्रा कल विधानसभा स्तर पर निकलेगी यात्राएं- भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस को धूम धाम से मना रही है जिसको लेकर 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक विभिन्न कार्यक्रम तय किए गए हैं। जिसके

## भाजपा की तिरंगा यात्रा से छत्तीसगढ़ में चारों ओर भारत माता के नारों की गूंज

प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जयसवाल, पूर्व मंत्री, विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में धूम धाम से निकली तिरंगा यात्राएं

अंतर्गत विधानसभा तिरंगा यात्रा बाइक रैली रायपुर की हर विधानसभा से निकाली जाएगी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा और साथ ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चलाया जायेगा जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक बुध में पहुंचेंगे और स्थानीय नागरिकों से अपने मकान और व्यवस्था पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने का आह्वान किया जायेगा। कार्यक्रमों की शुरुवात सोमवार 11 अगस्त से की जा चुकी है रायपुर शहर के 4 मंडलों माना मंडल, तत्यपारा मंडल, सदर बाजार मंडल और ग्रामीण मंडल के युवाओं ने आज बाइक रैली का आयोजन किया जिसमें आम जनमानस में जागरूकता लाने प्रेरित किया गया जिससे वे अधिक से अधिक संख्या में भारत के राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर अपनी सहभागिता निभाने आगे

आएँ। मंगलवार प्रातः 8 बजे कलेक्ट्रेट चौक पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की आदम कद प्रतिमा पर और आसपास स्वच्छता अभियान चला कर डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी साथ ही रायपुर उत्तर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा में शाम 4 बजे तिरंगा यात्रा बाइक रैली आयोजित की गई है उत्तर विधानसभा की तिरंगा यात्रा बाइक रैली में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति रहेगी यह बाइक रैली तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से शुरू होकर शारदा चौक पर समापन किया जायेगा, रायपुर ग्रामीण के कार्यक्रम का नेतृत्व विधायक मोती लाल साहू करेंगे रायपुर पश्चिम और दक्षिण विधानसभा की बाइक रैली 14 अगस्त को आयोजित की जायेगी

जो अपने अपने विधानसभा के मुख्य मार्गों का भ्रमण करेगी रायपुर पश्चिम में राजेश मृगत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा बाइक रैली के साथ ही रामनगर परिक्षेत्र से भारत माता चौक तक स्कूली बच्चों द्वारा विशाल तिरंगे के साथ पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी एवं भारत माता चौक पर भारत माता की आरती का कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा। साथ ही साथ 14 अगस्त रायपुर शहर जिला अंतर्गत आने वाले सभी बूथों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत स्थानीय नागरिकों को अपने निवास और व्यवस्थाओं पर तिरंगा लगाने हेतु प्रेरित करने भाजपा पदाधिकारी पैदल भ्रमण करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सुबह प्रदेश एवं जिला भाजपा कार्यालय में ध्वजा रोहण का कार्यक्रम आयोजित है ध्वजा रोहण कार्यक्रमों में प्रदेश एवं जिला भाजपा के विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं को उपस्थिति रहेगी।

## साय रायपुर और विस अध्यक्ष राजनांदगांव में करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। देशभर में 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में ध्वजारोहण करेंगे। केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। समारोह में पदक अलंकरण और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। समारोह स्थल से आजादी के शुभ अवसर पर रंगीन गुब्बारे छोड़े जाएंगे।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण देव को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शासकीय सेवकों की समस्याओं का निराकरण करने का आग्रह करना पड़ रहा है। इससे स्पष्ट है सरकार के काम काज से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन नाखुश है। दिख भी रहा है, भाजपा के नेता व विधायक, आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होने से आक्रोशित है। कई बार सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रकट कर चुके हैं। यह सब सरकार में बैठे नौसिखिया मंत्रियों के कारण हो रहा है। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यह हाल है तो आम जनता का तो भगवान मालिक है, यह सरकार न तो किसी के सुन रही है, न किसी के हित में काम कर रही है। 8 महीने में ही भाजपा की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। हर वर्य इस सरकार से हताश और परेशान है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व लंबित एरियर्स के भुगतान एवं अन्य मुद्दों के निराकरण के लिए आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ रही है। किसान खाद, बीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। युवा रोजगार के लिए अर्थनयन प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक संघ भी सरकार के युक्तियुक्तकरण के फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है।

## सरकार के काम काज से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन नाखुश है

रायपुर। विश्व हाथी दिवस पर इवेंट जीवी भाजपा सरकार के द्वारा राजधानी के पांच सितारा होटल में सरकारी आयोजन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है हसदेव के जंगलों में लाखों पर कटवाने वाली सरकार और हाथियों के प्राकृतिक आश्रय स्थल हसदेव अरण्य और तमोरपिंगला के जंगल को उजाड़ने वाले भाजपाई राजधानी रायपुर के पांच सितारा होटल में हाथी दिवस मनाकर मानव हाथी द्वंद्व के पीड़ित और प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा विधानसभा से पारित लेमरू एलिफेंट रिजर्व का प्रस्ताव रोक रखा है, और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर दिखावे के लिए विश्व हाथी दिवस का आयोजन राजधानी रायपुर के होटल में कर रही है जिसमें ना पीड़ित शामिल है नहीं कोई प्रभावित। हाथी मानव को कुचल रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भाजपा सरकार पांच सितारा होटलों में हाथी दिवस का जश्न मना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है।

## भाजपा क्या ऐसे रोकेंगे मानव हाथी द्वंद्व?

रायपुर। देश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार बप्पी राय, निशु त्रिवेदी, महेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह को आंध्र पुलिस के द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन पत्रकारों की तत्काल रिहाई करवाये और इनके खिलाफ घडयंत्र रचकर झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले थानेदार और माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाये। भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। थानेदार माफियाओं के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और जो पत्रकार इनके खिलाफ आवाज उठाता है उन पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसा कर गिरफ्तार कराया जाता है। उनकी आवाज को दबाया, कुचला जाता है। भाजपा सरकार में पत्रकारों को सवाल पूछने से रोका जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया था। साय सरकार बनते ही पत्रकार सुरक्षा कानून का मखौल उड़ाना जा रहा है। पत्रकार अब सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है वही पत्रकारों को झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सीमा में अंतरराष्ट्रीय तट माफिया की कारुगजारी को उजागर करने वाले पत्रकारों को झूठे मामलों में गिरफ्तार करवाया गया है।

## भाजपा सरकार में सुनियोजित तरीके से पत्रकारों का दमन किया जा रहा

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सोमवार को रायपुर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कावरे सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से राजस्व प्रकरणों की जानकारी तलब की। उन्होंने राजस्व संबंधी विवादित और अविवादित प्रकरणों के बंटकन के लिए अभियान चलाकर निपटारा करने और सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त कावरे ने कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनने और जल्द समाधान करने को कहा ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर ना काटना पड़े। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर ही पक्षकार को बुलाया जाकर प्रकरणों पर त्वरित आदेश पारित करें। संभागायुक्त ने बंटकन के लिए अभियान चलाकर निपटारा करने और सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश भी दिए।

## प्रमुख समाचार

## उपमुख्यमंत्री ने अमरकंटक में नर्मदा मैर्या और जलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा-अर्चना

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज सुबह अमरकंटक स्थित नर्मदा मैर्या मंदिर और जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने माँ नर्मदा और भगवान शिव से प्रदेशवासियों के लिए की सुख-शांति-समृद्धि की कामना की। उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कल अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था और स्वयं कांवड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया था। उन्होंने कांवड़ियों को भोजन का वितरण भी किया और उनके साथ

पवित्र सावन माह की इस महत्वपूर्ण की 150 किलोमीटर लंबी कांवड़ ताकि भक्तगणों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उनके निर्देशानुसार कांवड़ियों के लिए 15 से अधिक स्थानों पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिनमें 4 पुलिस पेट्रोलिंग टीमें और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की ड्यूटी शामिल है। पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कांवड़ियों के लिए 20 से अधिक स्थानों पर ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। अमरकंटक के

मृत्युंजय आश्रम में निःशुल्क भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है, जिसमें दाल-भात, सब्जी, मिठाई जैसे खीर, पुड़ी और हलवा का समावेश है। इन व्यवस्थाओं की निगरानी में बोलबल समन्वय समिति और स्थानीय अधिकारी सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारे लिए कांवड़ियों की सार्वजनिक सेवा के इस पवित्र अवसर पर हमने सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। ताकि सभी भक्तजन बिना किसी कठिनाई के अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के गौरव की बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण मार्गदर्शन और परियोजना निदेशक श्री आजीविका मिशन बिहान की सदस्य कौशल प्रसाद तेंदुलकर के नेतृत्व में आकांक्षी ब्लॉक गौरैया के ग्राम कोरजा की ज्योति पाल को 78 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। श्रीमती ज्योति पाल आयुषी स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं और चक्रवी निधि राशि एवं बैंक ऋण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय करती हैं। साल भर में इस व्यवसाय से लगभग एक लाख बीस हजार रुपए आमदनी हो जाती है। यह पहला मौका है जब जिले से किसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह की दीदी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

## गौरव बनी ज्योति पाल, स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हुई आमंत्रित

रायपुर। जीपीएम जिले के लिए यह कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के गौरव की बात है कि राष्ट्रीय ग्रामीण मार्गदर्शन और परियोजना निदेशक श्री आजीविका मिशन बिहान की सदस्य कौशल प्रसाद तेंदुलकर के नेतृत्व में आकांक्षी ब्लॉक गौरैया के ग्राम कोरजा की ज्योति पाल को 78 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। श्रीमती ज्योति पाल आयुषी स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं और चक्रवी निधि राशि एवं बैंक ऋण लेकर बकरी पालन का व्यवसाय करती हैं। साल भर में इस व्यवसाय से लगभग एक लाख बीस हजार रुपए आमदनी हो जाती है। यह पहला मौका है जब जिले से किसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह की दीदी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।